3 साल मोदी सरकार

सतत प्रयास, उत्साहजनक परिणाम

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

श्री राधा मोहन सिंह
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

श्री एस.एस. अहलुवालिया
कृषि एवं किसान कल्याण
और संसदीय कार्य राज्यमंत्री

श्री परशोत्तम रूपाला
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री

श्री सुदर्शन भगत
कृषि एवं किसान कल्याण
राज्यमंत्री

स्वस्थ धरा, खेत हरा

2016-17: Agricultural Growth Rate: 4.4%

Agri Research

596 high yielding climate resilient crop varieties/hybrids of field crops released during last three years.

Established **150 pulses seed hub** to produce quality pulse seeds.

Green Revolution

8.67% boost in foodgrains output

2015-16: 251.57 million tonnes yield
2016-17: 273.38 million tonnes yield

Agri Extension

Efforts for strengthening 669 KVKs by increasing the staff from 16 to 22 per KVK.

27% increase in trained candidates in 2014-17

18% increase in agriventures

Blue Revolution

In comparison to 2011-14, growth in fisheries production during 2014-17 is **20.1%**

Target to produce 15 million metric tonnes by 2020-21

Agri Education

Undergraduation in Agriculture & allied subjects declared as Professional degree.

Remuneration for research associates increased from ₹12000 to ₹15000/month in first 2 years & ₹14000 to ₹17500/month in final year.

5th Dean Committee Recommendations approved

White Revolution

In comparison to 2011-14, growth in milk production during 2014-17 is **16.9%**

Agriculture Budget Estimate & Expenditure

During UPA Government

Budget Year	Budget Estimate	Expenditure
2011-12	₹ 24,526 crore	₹ 23,290 crore
2012-13	₹ 28,284 crore	₹ 24,630 crore
2013-14	₹ 30,224 crore	₹ 25,896 crore

During Modi Government

Budget Year	Budget Estimate	Expenditure
2016-17	₹ 45,053 crore	₹ 57,503 crore

2016–2017 खाद्यान का रिकॉर्ड उत्पादन

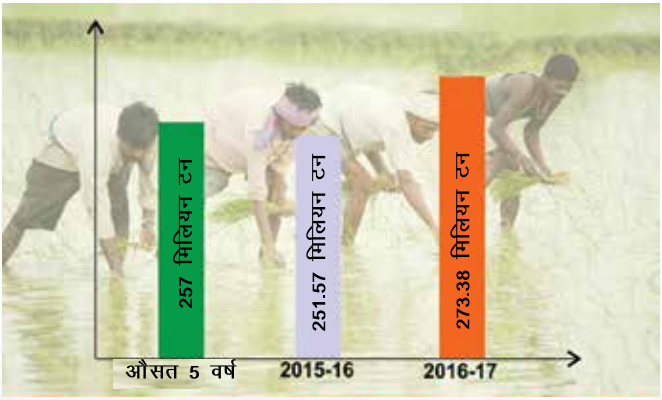

2016–17 का रिकॉर्ड खाद्यान उप्तादन पिछले 5 वर्ष के औसत से 6.37 प्रतिशत से अधिक है व पिछले वर्ष 2015–16 के उत्पादन से 8.67 प्रतिशत अधिक है।

मोदी सरकार द्वारा बजटीय आवंटन अधिक किया गया।

सॉयल हेल्थ कार्ड (एसएचसी)

- सॉयल हेल्थ कार्ड योजना फरवरी, 2015 में शुरू की गई थी।
- देश के सभी भूधारी किसानों को हर दो वर्ष में सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किये जाएंगे।
- खेत स्तर पर मिट्टी परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम।
- पोषक तत्वो के प्रयोग के लिए अनुकूलित फसल विशेष सिफारिश प्रदान करना।
- 2.80 करोड़ नमूने एकत्रित किये गये हैं जिसमें से 14 करोड़ कार्ड बनाए जा रहे हैं
- 7.1 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को 2 मई 2017 तक वितरित किये जा चुके हैं और शेष अगले 3 महीनों में वितरित किये जाएंगे।
- इसका द्वितीय चक्र 1 मई, 2017 से शुरू।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत जारी की गई धनराशि

वर्ष 2011–14 में राज्यों को जारी रुपये 27.76 करोड़ की राशि के मुकाबले वर्ष 2014–17 में रुपये 840.52 करोड़ जारी, इसमें 30 गुना वृद्वि है।

सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़ (राजस्थान) में किया गया।

मंजूर की गई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (अचल, चल, मिनी– प्रयोगाशालाएं)

वर्ष 2011–14 में केवल 15 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं थी जो बढ़कर वर्ष 2014–17 में 9063 हो गयी।

सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत जारी राशि

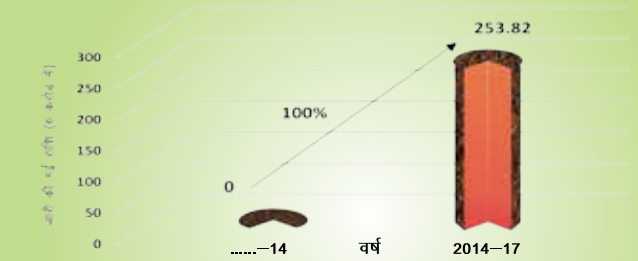

वर्ष 2014 तक कोई भी धनराशि सॉयल हेल्थ कार्ड को नहीं दी गई थी। 2014–17 के दौरान इस योजना के अर्न्तगत 253.82 करोड़ की राशि जारी की गई है।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

- किसान समूहों का गठन, किसानों का एकत्रीकरण, भूमि को जैव कृषि में परिवर्तन करने, वर्मीकंपोस्ट इकाई की स्थापना और जैव उत्पादों पर लेबल अथवा ब्रांड निशान लगाने के लिए सहायता।
- जैविक उत्पाद के संग्रहण और बाजार तक परिवहन के लिए प्रत्येक क्लस्टर को रू० 1,20,000 वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- समूह के प्रत्येक किसान को 3 वर्ष की अवधि के दौरान 50,000 रू० प्रति हैक्टेर की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। 20 हैक्टेयर के 10,000 जैविक क्लस्टरों को विकसित किया जायेगा ताकि 3 वर्षों के दौरान 2 लाख हेक्टेयर तक प्रमाणित क्षेत्र को कवर किया जा सके। अभी तक 9,186 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं।
- सरकार द्वारा परम्परागत संसाधनों, अनुकूल पर्यावरण हितैषी, कम लागत प्रौद्योगिकियों और अधिक लाभ आदि के उपयोग के साथ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।

17 जनवरी 2016, को गंगटोक, सिक्किम में राष्ट्रीय जैविक सम्मेलन का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

बजट अनुमान (पीकेवीवाई)

परंपरागत कृषि विकास योजना केन्द्र सरकार की पहली व्यापक योजना है। अबतक 9186 समूहों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है।

जैविक खेती के अर्न्तगत क्षेत्र

वर्ष 2011–14 के अनुपात में वर्ष 2014–17 के दौरान जैविक खेती के क्षेत्रफल में 176 प्रतिशत वृद्वि हुई।

उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक वैल्यू चेन विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)

- केन्द्रीय क्षेत्र की यह योजना वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक 3 वर्षों के लिए रुपये 400 करोड़ के परिव्यय के साथ 11 जनवरी, 2016 को शुरू की गई थी। यह योजना असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय एजेंसी के माध्यम से लागू की गई है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 0.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शमिल किया जाना है।
- इस योजना के अन्तर्गत अच्छी प्रगति करते हुए अबतक 2321 किसान समुह व 8 किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण किया जा चुका है।

मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–17 के दौरान निर्मुक्त राशि

वर्ष 2014–17 के दौरान एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत बज़ट में भारी वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम)

- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) योजना, देश की 585 विनयमित थोक मंडियों को एक ई–प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए 200 करोड़ के प्रारंभिक आबंटन के साथ 1 जुलाई, 2015 को अनुमोदित की गई।
- अब तक 13 राज्यों की 417 मंडियों को ई–नाम के साथ एकीकृत किया गया है।
- 16 राज्यों की 542 मंडियों को ई–नाम के साथ जोड़ने के लिए सिद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है ।
- ई–नाम पर व्यापार के लिए जांच करने में सुविधा हेतु 69 जिंसों के लिए मानक मापदंड विकसित किये गये हैं।
- 15 मई, 2017 तक 19,802.98 करोड़ रुपये के 83.57 लाख टन कृषि उत्पाद ई–नाम पर विपणित किये गये है। इसके अलावा 45,45,850 किसान, 89,934 व्यापारी और 46,411 कमीशन एजेंट ई–नाम प्लेटफार्म पर पंजीकृत किए गये हैं।
- संबंधित पोर्टल अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, तेलगू और बंगाली में उपलब्ध है। इसका मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।

कृषि विपणन सुधार

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पुराने मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 की जगह एक नये ''मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन (प्रोत्साहन और सुविधा) अधिनियम 2017'' का मसौदा तैयार किया है। इस अधिनियम को माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2017 को राज्यों को अपनाने के लिए जारी किया गया।

14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री ने 8 राज्यों के 21 मंडियों में ई–नाम की पायलेट परियोजना का शुभारंभ किया।

लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)

उद्यम पूंजी योजना (वी सी ए)

ग्रामीण आय और रोजगार में वृद्धि के लिए, कृषि व्यवसाय परियोजना स्थापित करने में निजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिये उद्यम पूंजी सहायता योजना को कृषि व्यवसाय विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

इक्विटी अनुदान योजना (ई जी एस)

इक्विटी आधार का समर्थन करने के लिए, वर्ष 2014–17 के दौरान अधिकतम 10 लाख रुपये तक की इक्विटी अनुदान फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी (एफपीसी) को दिया जाता है, इक्विटी अनुदान 94 किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को दिया गया है।

क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (सीजीएफएस)

क्रेडिट गारंटी फंड में बैंक द्वारा बढ़ाए गए ऋण के लिए फार्म से प्रोडयूसर कंपनी एफपीसी को बिना गारन्टी के 85 प्रतिशत को कवर करके; अधिकतम 1.00 करोड़ रुपए तक प्रदान किया गया है। वर्ष 2014–17 के दौरान, कुल 21 एफपीसी ने इस योजना के तहत लाभ लिया है।

उद्यम पूंजी योजना (वी सी ए) के अर्न्तगत स्थापित किए गये परियोजनाएं

पिछले 3 वर्षों (2011–14) के दौरान 459 के मुकाबले 2014–17 के दौरान 773 वीसीए परियोजनाएं स्थापित की गईं जो 68.40 प्रतिशत की वृद्वि है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन

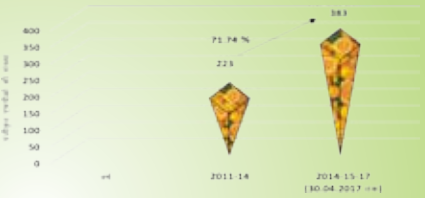

वर्ष 2011–14 के दौरान 223 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के मुकाबले 2014–17 में 383 एफपीओ पंजीकृत किये गये जिसमें 71.74 प्रतिशत वृद्वि हुई है।

नेफेड की उपलब्धियां

कपास, दालों और तिलहनों के 16 चिन्हित कृषि वस्तुओं की खरीद के लिये नेफेड एक केंन्द्रीय नोडल एजेंसी है।

वर्ष 2016–17 के दौरान नेफेड ने 877222. 09 मेट्रिक टन दालों की उच्चतम खरीदारी की और विगत दो दशकों में उच्चतम् रूपये 132.69 करोड़ का सर्वोच्च सकल लाभ दर्ज किया गया।

2011–14 के दौरान की तुलना में नेफेड द्वारा वर्ष 2014–17 में दालों, तिलहनों एवं अन्य वस्तुओं की खरीद में काफी सुधार हुआ।

नेफेड के द्वारा खरीद से लाभान्वित कृषक

वर्ष 2011–14 के बीच 270352 की तुलना में वर्ष 2014–17 के दौरान खरीद से 373071 किसान लाभान्वित हुए जोकि 172% अधिक है।

नेफड के व्यवसाय में वृद्वि

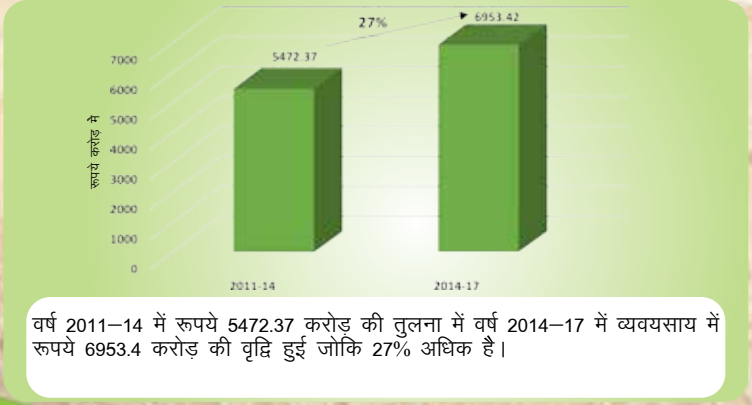

वर्ष 2011–14 में रूपये 5472.37 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014–17 में व्यवयसाय में रूपये 6953.4 करोड़ की वृद्वि हुई जोकि 27% अधिक है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

- सभी खाद्यान्न, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं।
- एक मौसम एक दर – खरीफ के लिए 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अधिकतम है।
- फसल उपज के सभी जोखिमों – फसल बुआई के पूर्व, फसल के दौरान तथा फसल कटाई के बाद के सभी जोखिम शामिल।
- ओलावृष्टि, भूस्खलन और जलभराव से हुए नुकसान के लिए प्रत्येक खेत स्तर पर क्षति का आंकलन करना।
- फसल कटाई से अधिकतम 14 दिन की अवधि में चक्रवात/चक्रवात वर्षा एवं बेमौसम बारिश के विशेष आपदा के कारण हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति।
- प्राकृतिक आपदा के कारण संरक्षित बुआई के लिए बीमित राशि 25 प्रतिशत तक का अग्रिम भुगतान।

फसल बीमा योजना के तहत शमिल किसान

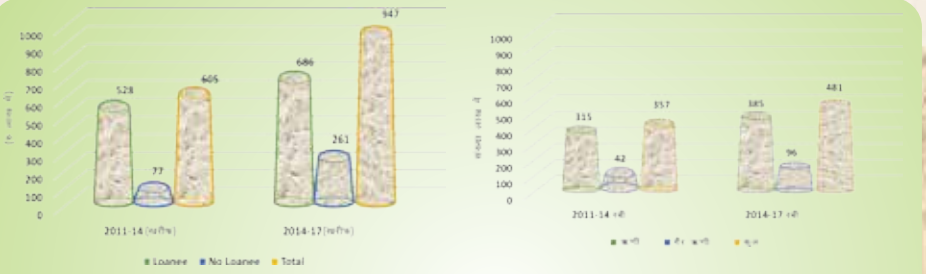

खरीफ मौसम

2011–14 खरीफ मौसम की तुलना में 2014–17 में ऋणी व गैर ऋणी किसानों के कुल अच्छादन में 56.52 प्रतिशत की वृद्वि। उल्लेखनीय है कि गैर ऋणी किसानों के अच्छादन में 238.96 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

रबी मौसम

2011–14 रबी मौसम की तुलना में 2014–17 में ऋणी व गैर ऋणी किसानों के कुल अच्छादन में 34.73 प्रतिशत की वृद्वि। उल्लेखनीय है कि गैर ऋणी किसानों के अच्छादन में 128.50 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

कृषि ऋण एवं ज्वाइंट लाईबिलिटी ग्रुप

कृषि ऋण

(क) आधारभूत कृषि ऋण प्रवाह (अल्पकालिक फसल ऋण एवं सावधि ऋण)

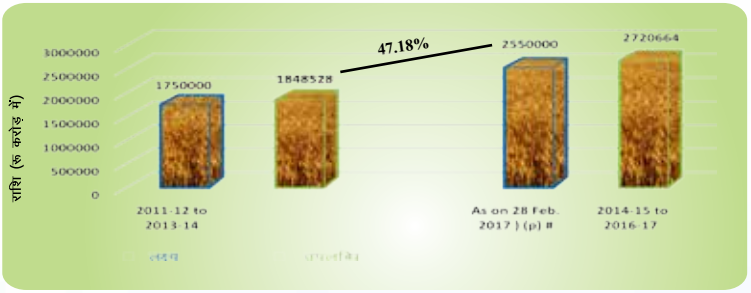

वर्ष 2011–14 की तुलना में 2014–17 के दौरान आधारभूत कृषि ऋण प्रवाह में 47.18% वृद्धि हुई।

(ख) कृषि ऋणः अल्पकालिक फसल ऋण

वर्ष 2011–14 की तुलना में वर्ष 2014–17 के दौरान 35.63% अल्पकालिक ऋण मे वृद्धि हुई है।

ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप

ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप का गठन

वर्ष 2007 से 2014 तक मात्र 6.72 लाख ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनाकर 7 वर्ष में रु. 6630 करोड़ की राशि दी गई जबकि 2014–17 तीन वर्षों में 15.85 लाख ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप बनाकर रु. 16268 करोड़ राशि दी गई।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)–सूक्ष्म सिचाई

- **प्रत्येक बूंद अधिक फसल** के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान सरकार द्वारा अधिक धनराशि देकर अधिक क्षेत्रफल को सिंचित किया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई हेतु को जारी की गई राशि

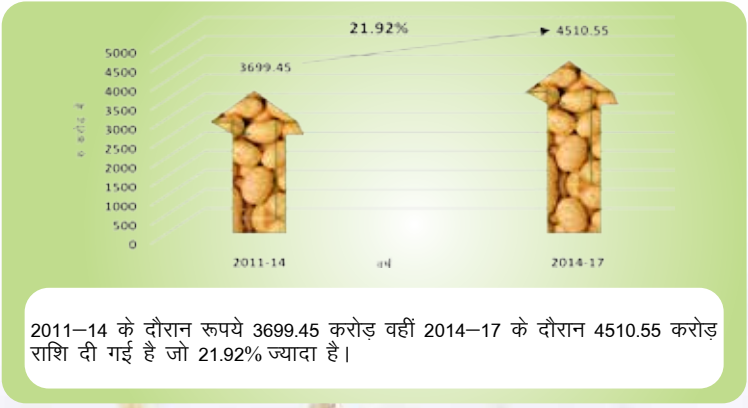

2011–14 के दौरान रूपये 3699.45 करोड़ वहीं 2014–17 के दौरान 4510.55 करोड़ राशि दी गई है जो 21.92% ज्यादा है।

सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि (ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर)

2014–17 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र (ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर) में साल दर साल वृद्धि दर्ज की गई।

बागवानी विकास

बागवानी विकास मिशन

वर्ष 2011–14 एवं 2014–17 के दौरान एमआईडीएच के प्रमुख घटक के तहत उपलब्धि

वर्ष 2011–14 की तुलना में वर्ष 2014–17 के दौरान एमआईडीएच के अर्न्तगत प्रमुख घटकों में विशेष उपलब्धि रही है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने पूरे देश में 3100 शीत भंडारण प्रोजेक्ट को सहायता दी जिसमें भंडारण क्षमता 140.10 लाख मी. टन है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड ने 32 शीत भंडारण प्रोजेक्ट को सहायता दी जिसकी क्षमता 1.88 मी. लाख मी. टन है।
- वर्ष 2017–18 के दौरान बोर्ड ने 3 लाख मेट्रिक टन शीत भंडारण क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा तकनीकी प्रसार के लिए 674 प्राजेक्ट की सहायता दी गई जिससे वर्ष 2016–17 में 127 प्रोजेक्ट सम्मिलित है।
- बोर्ड ने उतम गुणवता पौधारोपण पैदावार के लिए 1591 नर्सरियों को सत्यापित किया गया।

बागवानी विकास

जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज

- जम्मू–कश्मीर में क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्रों के पुनरूस्थापन और बागवानी विकास के लिए 07.11.2015 को 500 करोड़ रूपए के विषेश पैकेज की घोषणा की गई।
- जम्मू–कश्मीर सरकार ने 2016–17 से 2018–19 के लिए 500 करोड़ रूपए की 3 वर्ष की कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसे केबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एमआईडीएच लागत मानदंडों के लिए एक मुश्त छूट का अनुमोदन किया:
  - 460 रूपए प्रति पौध की अधिकतम लागत पर रोपण सामग्री का आयात।
  - 9.8 लाख प्रति हैक्टेयर की दर पर वायर टेरिल सिस्टम का आयात।
  - रोपण सामग्री के प्रावधान हेतु 90 प्रतिशत की दर पर राज्य सहायता को बढ़ाया गया।
- सीसीईए निर्णय के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति 08.12.2016 को जारी की गयी है।
- वर्ष 2016–17 में 47.89 करोड़ रूपए (भारत सरकार का हिस्सा) जारी किया गया।

केसर पार्क

- 24.45 करोड़ रुपये की कुल लागत से पम्पोर पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) में केसर पार्क स्थापित करने का कार्य एनएचबी को सौंपा है। पार्क में गुणवत्ता नियंत्रण लैब, निर्यात प्रोत्साहन कार्यकलाप और ई–नीलामी केंद्र की सुविधा होगी।
- केसर पार्क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। प्रदान की गई प्लांट और मशीनरी स्थापित करने हेतु तैयार है।
- केसर पार्क के अक्टूबर 2017 के दौरान शुरू हो जाने की संभावना है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी ने 23 अगस्त 2014 को केसर पार्क का पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर में शिलान्याास किया था।

नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)

- वर्ष 2011–14 के दौरान सीडीबी ने 7 न्यूक्लियस नारियल बीज उद्यान, 39 छोटे नारियल नर्सरी एवं 295 जैविक खाद इकाइयां स्थापित कीं जबकि 2014–17 में सीडीबी ने 15 न्यूक्लियस नारियल बीज उद्यान, 90 छोटे नारियल नर्सरी एवं 331 जैविक खाद इकाइयां स्थापित कीं।
- वर्ष 2014–15 में योजना शुरु होने के बाद से 2601 नीरा तकनीशियन को प्रशिक्षित किया गया।
- वर्ष 2011–14 के दौरान 6934 हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 8851 हेक्टेयर क्षेत्र को नये बागान के अंतर्गत लाया गया।
- वर्ष 2011–14 की तुलना में 2014–17 के दौरान नारियल तेल के निर्यात में 68% वृद्वि हुई है।
- नई विदेश व्यापार नीति 2015–20 में नारियल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनके निर्यात (एफओबी) मूल्य का 5% तक प्रोत्साहन के रूप में दिया गया है।
- परिणामस्वरूप इस वित्तीय वर्ष 2016–17 की शुरूआत से ही भारत नारियल तेल का निर्यात मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका को करने लगा है, जबकि हम पिछले वर्ष तक इन्हीं देशों से नारियल तेल का आयात कर रहे थे।
- पहली बार भारत शुष्क नारियल का बड़ी मात्राओं में निर्यात अमेरिका और युरोपीय देशों को कर रहा है।

नारियल विकास की विभिन्न घटकों में उपलब्धि

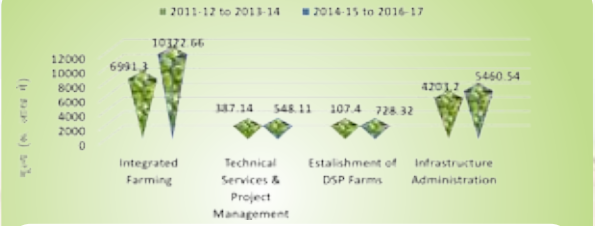

नारियल विकास के विभिन्न घटकों में नारियल विकास बोर्ड द्वारा पिछले 3 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गयी है।

नारियल उत्पादक संघ, फैडरेशन तथा नारियल उत्पादक कम्पनी

पिछले 3 वर्षों में नारियल उत्पादक संघ, फैडरेशन तथा नारियल उत्पादक कम्पनीयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी)

मधुमक्खी पालन

- 31 मार्च, 2017 तक 10.86 लाख कॉलोनियों सहित 6636 मधुमक्खी पालकों/मधुमक्खी पालन एवं मधु सोसाइटियों/ फर्मों/कंपनियों आदि को पंजीकृत किया गया।

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जारी/आवंटित निधियां

वर्ष 2011–14 की तुलना में पिछले 3 वर्षों (2014–17) में मधुमक्खी पालन के लिए बजट में लगभग 205.19% की वृद्धि।

कुल शहद उत्पादन

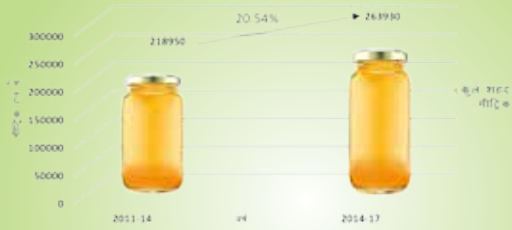

राष्ट्रीय बी बोर्ड द्वारा मधुमक्खी पालकों/किसानों को अन्य मदद/सहायता देने के कारण तैयार शहद एवं शहद उत्पादों ने वर्ष 2011–14 की तुलना में पिछले तीन वर्षों (2014–17) में 20.54% की वृद्धि।

कृषि वानिकी उपमिशन

- किसानों की आय को बढ़ाने और जलवायु अनुकूलता के लिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तैयार की गई।
- वर्ष 2016–17 के दौरान **''हर मेंड़ पर पेड़''** के लक्ष्य के साथ एक समर्पित योजना ''राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना'' की शुरूआत की गई।
- वर्ष 2016–17 में 50 करोड़ रूपए के केन्द्रीय हिस्से का बजट आवंटित।
- कृषि वानिकी उपमशिन (एसएमएएफ) के तहत सहायता के लिए पूर्वापेक्षा में ट्रानसिट विनिमयन की छूट
- 13 राज्यों (2016–17 में 8 एवं 2017–18 में 5) ने इस विनियमन में छूट प्रदान की है। अन्य राज्यों को भी इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है।

कृषि वानिकी विकास के लिए जारी धन राशि (रू. लाख)

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गयी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

दलहन

दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गए कदम

- धान की परती भूमि वाले क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत लाने के लिए रबी 2016 से आरकेवीवाई के अंतर्गत "दलहन के लिए पूर्वी भारत में चावल की परती भूमि वाले क्षेत्रों को लक्षित करना" नामक विशेष स्कीम की शुरूआत की गई है।
- धान खेतो के मेड़ो पर अरहर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- 2016–17 के 574 केवीके के माध्यम से 31000 क्लस्टर फ्रंट लाईन प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
- एसएयू/केवीके/आईसीएआर संस्थानों के 150 सीड हब स्वीकृत किए गए है।
- खरीफ 2016 से गुणवत्ता बीज उत्पादन के लिए एनएफएसएम के दलहन घटक का 15 प्रतिशत आवंटन निर्धारित किया गया।
- उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप दाल उत्पादन जो वर्ष 2015–16 में 16.35 मिलियन टन था। वह वर्ष 2016–17 में 35.81 प्रतिशत वृद्वि के साथ 22.14 मिलियन टन हुआ।

राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पॉम मिशन

तिलहन

- एनएमओओपी का लक्ष्य 2016–17 के अंत तक तिलहन के उत्पादन को 28.93 मिलियन टन से बढ़ाकर 35.51 मिलियन टन तक करना है।
- खरीफ 2016 से पानी ले जाने वाले एचडीपीई पाइपों के लिए सब्सिडी में 25/– रूपये से 50/– रूपये प्रति मी., पीवीसी पाइपों और एचडीपीई लेमिनेटेड फ्लैट बिछाई जाने वाली ट्यूबों के लिए 20/– से 35/– रूपये प्रति मी. बढ़ोत्तरी की गई है।
- प्रमाणित बीज वितरण के लिए बीज सब्सिडी में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्वि की गई है।

पूर्वी राज्यों में धान के पड़ती क्षेत्रों में तिलहनों और दालों को बढ़ावा

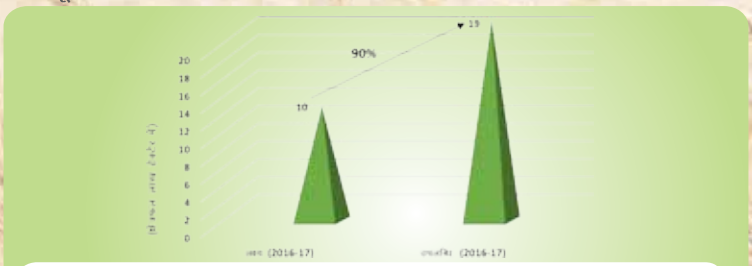

पूर्वी राज्यों में धान के परती क्षेत्र में तिलहनों और दालों के क्षेत्र में 90 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

देश में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा

- एनएमओओपी का उद्देष्य ताजे फल के गुच्छों (एफएफबी) की उत्पादकता में सुधार पर ध्यान देने के लिए ऑयल पाम के तहत 1.25लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- सीपीओ का अंतरराश्ट्रीय मूल्य 800 डॉलर से नीचे गिरने पर आयल पाम उत्पादकों को बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के माध्यम से एफएफबी की कीमतों का आश्वासन दिया गया।

12 अप्रैल, 2017 का कैबिनेट निर्णय

- **निर्णय 1:** आयल पाम की खेती की सहायता के तहत बड़े पैमाने पर आयल पाम के तहत 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।
- **निर्णय 2:** ऑयल पाम के घटकों, जैसे रोपण सामग्री, रखरखाव लागत, अन्तः फसल और बोर–वेल के लिए उन्नत सहायता

ऑयल पाम विकास के लिए विभिन्न घटकों में सहायता में बढ़ोतरी

ऑयल पाम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों में पर्याप्त वृद्वि की गई है।

पौध संरक्षण

गत् तीन वर्षों में किये गये सुधार कार्यः–

- लखनऊ, बागडोगरा, गोवा और पोर्ट ब्लेयर में चार नये पौध संगरोध स्टेशन शुरू किये गये हैं।
- ''एकल खिड़की प्रणाली''के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 51 पीक्यू आई एस स्टेशनों पर पीक्यूआईएस के साथ सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम का समेकन आयात निकासी के लिए ऑनलाइन मैसेज आदान प्रदान के जरिये लागू किया गया है।
- पादप स्वस्थता प्रमाण पत्रों को ऑन लाइन जारी करना अग्रिम स्थिति पर है। ई–पादप जारी करने के लिए पादप स्वस्थता प्रमाणपत्र जारीकर्ता अधिकारी का डिज़िटल हस्ताक्षर तैयार किया जा रहा है।

पौध संरक्षण कीटनाशी निर्यात पंजीकरण

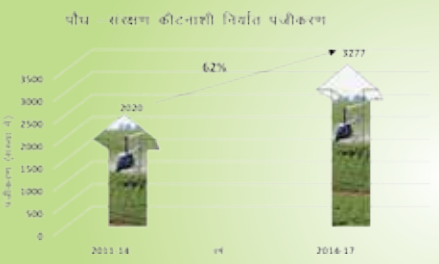

वर्ष 2011–14 की तुलना में वर्ष 2014–17 में कीटनाशी निर्यात पंजीकरण में 62% की बढ़ोत्तरी

पौध संरक्षण कीटनाशी पंजीकरण

तकनीकों के उपयोग और उत्तम निरीक्षण से कीटनाशक पंजीकरण में 210% की बढ़ोत्तरी

कृषि यंत्रीकरण

किसानों को वितरित मशीनों की संख्या

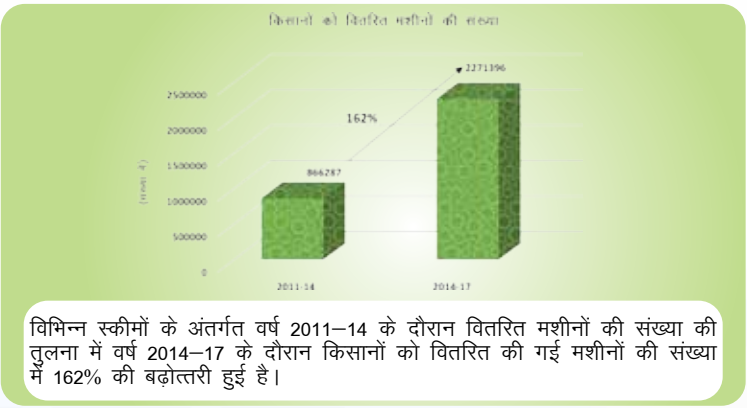

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2011–14 के दौरान वितरित मशीनों की संख्या की तुलना में वर्ष 2014–17 के दौरान किसानों को वितरित की गई मशीनों की संख्या में 162% की बढ़ोत्तरी हुई है।

निधि आबंटित

वर्ष 2011–14 के दौरान कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के लिए आवंटित निधि की तुलना में वर्ष 2014–17 में कुल 527% अधिक राशि आबंटित की गई।

बीज

बीज प्रभाग की पहलें एवं उपलब्धियां

- विभाग ने बीटी कपास संकर बीजों का अधिकतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) नियमन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत कपास निधि नियंत्रण आदेश 2015 पहली बार जारी किया। खरीफ 2016 के लिए बीटी कपास का अधिकतम विक्रय मूल्य निम्नवत है:–

Ckhth 1 dikl	Ckhth 2 dikl
#i;s 635@& ¼thjks xq.koRrk dher½ 450 xzke iSdsV ds lkFk	#i;s 800@& ¼49@& #i;s xq.koRrk dher½ 450 xzke iSdsV ds lkFk

- खरीफ 2017 में बीटी कपास बीजों का अधिकतम मूल्य खरीफ 2016 के समतुल्य रखा गया।
- पिछले 3 वर्षों में 96,778 बीज ग्राम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें 66.56 लाख किसानों को शामिल करते हुए 316.31 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया।
- खाद्य और कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधन (आईटीपीजीआरएफए) पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बहुपक्षीय प्रणालियों के तहत जर्म–प्लाजम/पौध अनुवांशिक संसाधनों के अंतरण हेतु प्रस्ताव की जांच की गई तथा विभिन्न देशों में निर्यात के लिए विभिन्न फसलों की 3158 किस्मों की सिफारिश भी की गई।

बीज प्रभाग की पहलें एवं उपलब्धियां

भारत सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक रही।

राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी)

- 2014–15 से 2016–17 की अवधि के दौरान कृषि फसलों की 661 और बागवानी फसलों की 136 किस्में जारी और अधिसूचित की गई ।
- 2014–15 से 2016–17 की अवधि के दौरान एक्जिम समिति द्वारा निर्यात के लिए 528 और बीज तथा रोपण सामग्री के आयात के लिए 579 मामलों की सिफारिश की गई ।

राष्ट्रीय बीज निगम के कारोबार में वृद्धि

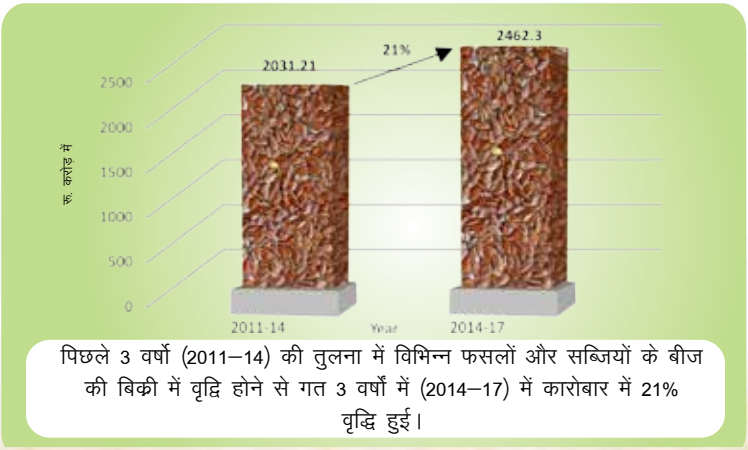

पिछले 3 वर्षो (2011–14) की तुलना में विभिन्न फसलों और सब्जियों के बीज की बिक्री में वृद्वि होने से गत 3 वर्षों में (2014–17) में कारोबार में 21% वृद्धि हुई।

पौध किस्मों के संरक्षण एवं किसानों के अधिकार

पौध किस्मों के संरक्षण एवं किसानों को लाभ प्रदान करने की नई पहलें

- हाल ही में पीपीवी एवं एफआर प्राधिकरण की तीन नई शाखा कार्यालय स्थापित करने का अनुमोदन किया गया पहला पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) में जो उत्तरी पहाड़ी राज्यों को कवर करेगा, दूसरा पुणे (महाराष्ट्र) में जो मध्य और पश्चिमी राज्यों को कवर करेगा और तीसरा शिवमोगा (कर्नाटक) दक्षिणी राज्यों के लिए है।

पीपीवी एवं एफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किस्मों और आवेदन में वर्ष 2011–14 के मुकाबले वर्ष 2014–17 में 120 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पीपीवी व एफआर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किस्मो की संख्या

पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किस्मों में वर्ष 2011–14 के मुकाबले वर्ष 2014–17 में 164 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

19 अप्रैल, 2017, को माननीय कृषि मंत्री द्वारा मोतिहारी पूर्वी चंपाराण (बिहार) में 5 पौध जीनोम उद्वारकर्ता सामुदायिक पुरस्कार, 10 पौध जीनोम उद्वारकर्ता किसान रिवार्ड और 20 पौध जीनाम उद्वारकार्ता किसान पुनर्गठन पुरस्कार प्रदान किये गये।

महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी)

महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पुर्वानुमान केन्द्र (एमएनसीएफसी) द्वारा निम्नलिखित प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं:

- चमन (समन्वित बागवानी आंकलन एवं जियो–इंफोरमेटिक्स का प्रयोगिक प्रबंधन)
- फसल (अंतरिक्ष का उपयोग कर कृषि उत्पादन पूर्वानुमान, कृषि–मौसम विज्ञान और भूमि आधारित पर्यवेक्षण)
- एनएडीएएमएस (राष्ट्रीय कृषि सूखा आंकलन और निगरानी प्रणाली
- केआइएसएन (सी केरोप बीमा अंतिरक्ष प्रौद्योगिकी और जियो इनफोर्मेटिक का उपयोग)
- धान के परती क्षेत्रों में फसल सघनीकरणं

बागवानी फसलों की जिला स्तरीय सूची

बिहार के दरभंगा जिले में मखाना की खेती के लिए प्रमुख गावों की पहचान

सूखा प्रबंधन–आपदा राहत उपायों में परिवर्तन

- सभी श्रेणी की सहायता मापदंड 1.5 गुना बढ़ाए गए है।
- मानकों में परिवर्तन कर किसानों को 50% फसल हानि के स्थान पर केवल 33% फसल हानि पर ही आपदा राहत के तहत सहायता।
- सभी मामलों में सहायता की ग्राह्यता को 1 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दिया गया।
- किसानों की मृत्यु होने पर प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 1.5 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई।

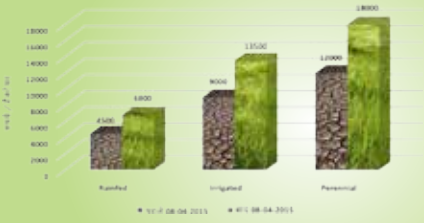

सभी श्रेणी की सहायता मापदंड 1.5 गुना बढ़ाए गए है।

- प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता देने के लिए पहली बार यूटी–डीआरएफ फंड रूपये 50 करोड़ रखा गया है।

राज्य आपदा अनुक्रिया कोष के अंतर्गत राज्यों को प्राकृतिक आपदा निधियों का आबंटन

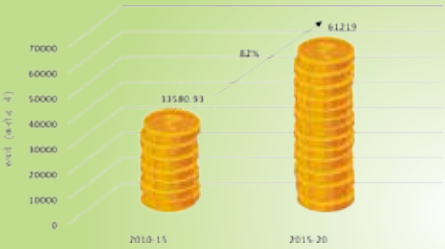

वर्ष 2011–2014 की तुलना में वर्ष 2014–17 में राज्यों को प्राकृतिक आपदा निधियों का आबंटन में 82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्राकृति आपदा और एनडीआरएफ के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को अनुमोदित केन्द्रीय सहायता

2011–2014 में स्वीकृत रूपये 9068.72 करोड की तुलना में 2014–17 में रूपये 29194.00 करोड की मंजूरी दी गई, जो कि 221 प्रतिशत अधिक है। जबकि कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी प्रदेशों के लिए यह विचाराधीन है।

कृषि व्यापार

कृषि निर्यात बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम

- 28.03.2017 से गेंहु पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 28.03.2017 से तूर (अरहर) आयात शुल्क को बढ़ाकर 0 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- 27 मार्च, 2017 से पैकेजिंग प्रतिबंधों की समीक्षा करके खाघ तेल (तिल, मुगफली, सोयाबिन और मक्का तेल) के लिए निर्यात प्रतिबंध को शिथिल किया गया है।
- 17.09.2015 से कच्चे खाघ तेल पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत और परिशुद्व खाघ तेल पर 15 से 20 प्रतिशत किया गया।
- 30.04.2015 से चीनी पर आयात शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

प्रमुख कृषि किस्मों का निर्यात (2011–14 से 2014–17)

सरकार की निर्यातोन्मुखी नीतियों के कारण कपास, ताजे फलों सब्जियों चावल (गैर–बासमती), चावल (बासमती) के निर्यात में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सहकारिता के समग्र विकास हेतु सहकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है। जिसमें सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण शामिल है।

एनसीडीसी द्वारा अभूतपूर्व निर्गमित राशि

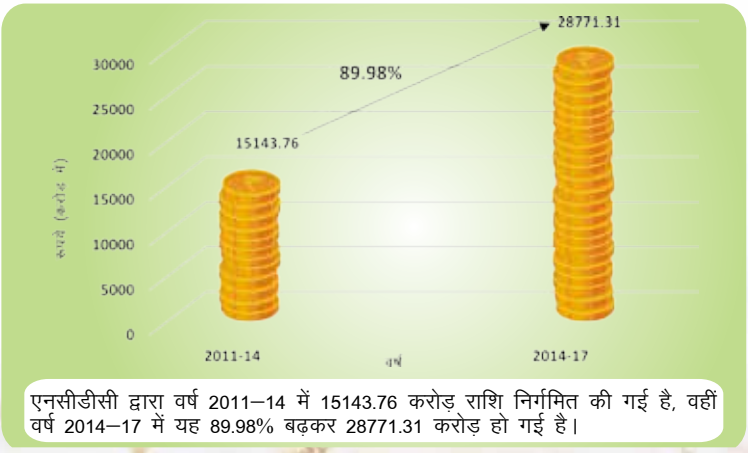

एनसीडीसी द्वारा वर्ष 2011–14 में 15143.76 करोड़ राशि निर्गमित की गई है, वहीं वर्ष 2014–17 में यह 89.98% बढ़कर 28771.31 करोड़ हो गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास

सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किसानों की सुविधा के लिए निम्नलिखित मोबाइल एप तैयार किए गए है

- किसान सुविधा
- पूसा कृषि
- फसल बीमा
- फसल बीमा पोर्टल
- एग्रीमार्केट
- सीसीई कृषि

कृषि में कौशल विकास

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2016–17 के दौरान पहली बार आईसीएआर के विस्तार प्रभाग और भारतीय कृषि कौशल परिषद के सहयोग से आरकेवीवाई से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान कौशल प्रशिक्षण के लिए भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा 100 केवीके और 8 प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी गई है।
- वर्ष 2016–17 के दौरान 216 कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए रुपये 3.52 करोड़ स्वीकृत किये गये जिसमें से 206 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण के लिए एएससीआई ने 168 क्वालीफिकेशन पैक (क्यूपीएस) विकसित किये।

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा नई दिल्ली में 5 जनवरी, 2017 को आयोजित ''कौशल विकास से कृषि विकास'' राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यशाला

मैनेज हैदराबाद के सहायता से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दक्षिण राज्यों के लिए 20 फरवरी, 2017 को हैदराबाद में क्षेत्रीय कौशल विकास कार्यशाला आयोजित

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)

- कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राज्य को और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2014–15 में संशोधित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की है।
- दलहनों एवं तिलहनों के लिए चावल की खाली भूमि लक्षित उप स्कीम आरकेवीवाई के अन्तर्गत एक विशेष स्कीम के रूप में वर्ष 2016–17 में आरंभ की गयी है। इस उप स्कीम के लिए आवंटित राशि 50 करोड़ रुपये है।
- मृदा अम्लता, क्षारता और लवणता की समस्या से संबंधित एक उप स्कीम समस्या ग्रस्त मृदा का सुधार आरकेवीवाई के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से शुरू की गयी है। इस उप स्कीम के लिए आवंटित राशि 50 करोड़ रुपये है।
- कृषि के समेकित विकास के लिए सार्वनिक–निजी भागीदारी के अन्तर्गत महाराष्ट्र, कनार्टक ने वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान 5 परियोजनाए शुरू की है।
- सूखा प्रमाणित राज्यों में पशुओं की चारा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आरकेवीवाई के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौरान राज्यों के लिए 78.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजना

SERI = Sericulture, Other = Innovative Programme, NONF = Non Farm Activities, ITEC = Information Technology, AGRE = Agri/Horti/Animal Husbandary

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा राज्यों की विभिन्न परियोजना में वृद्वि दर्ज हुई है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

द्विपक्षीय सहयोग (एमओयू/एमओसी/समझौते/कार्य योजना)

- कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 9 देशों के साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग आधारित समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किए हैं–आरमेनिया, मेडागास्कर, लिथुनिया, जापान, क्रिगिस्तान, पुर्तगाल, केन्या, मारीशस और संयुक्त राज्य अमीरात।
- 18.08.2015 को भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाघ कार्यक्रम पर और 07.11.2016 को ग्लोबल फसल विविधता ट्रस्ट (जीसीडीटी) बोन जर्मनी संबधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ;

- ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठकः नई दिल्ली में 23 सितम्बर, 2016, को ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की छठी बैठक सफलतापुर्वक आयोजित की गई।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10–11 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में एफआईसीसीआई (FICCI) के सहयोग से इण्डिया–अफ्रीका एग्रीबिजनेस फोरम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था जिसमें कई मंत्रियों, सरकारी कर्मियों और कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

स्वच्छता पखवाड़ा

एक कदम स्वच्छता की ओर

- 16 से 31 अक्टूबर 2016 के पखवाड़े के दौरान स्वच्छ भारत अभियान में 271 मण्डियों को शामिल किया गया था और संबद्ध कार्यालयों के साथ साथ कृषि भवन मुख्यालय में सफाई अभियान आयोजित किए गए।
- ई–नाम योजना के तहत अपशिष्ट प्रबंधन योजना की स्थापना के लिए प्रत्येक मण्डी के लिए 5 लाख रू. प्रति मण्डी के प्रावधान का निर्णय लिया गया।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उपयोजना के रूप में कृषि योजना में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तैयार करने का निर्णय लिया गया था। जिसके लिए राज्यों को निर्मुक्ति के लिए उस उप–योजना के तहत आरकेवीवाई के आवंटन का 1 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ 27.10.2016 को एक वीडियों कांफ्रेस आयोजित की गई थी और उन्हें ''स्वच्छ पखवाड़ा कार्यकलापो'' के बारे में संक्षेप में बताया गया था। उन्हें कंपोस्ट फार्म अपशिष्ट तैयार करने के लिए उनकी विद्यमान योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान का अनुरोध किया गया।
- इस विभाग के विभिन्न कार्यालयों एवं कृषि मंडियों में 16 से 31 मई, 2017, के दौरान पुनः स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।

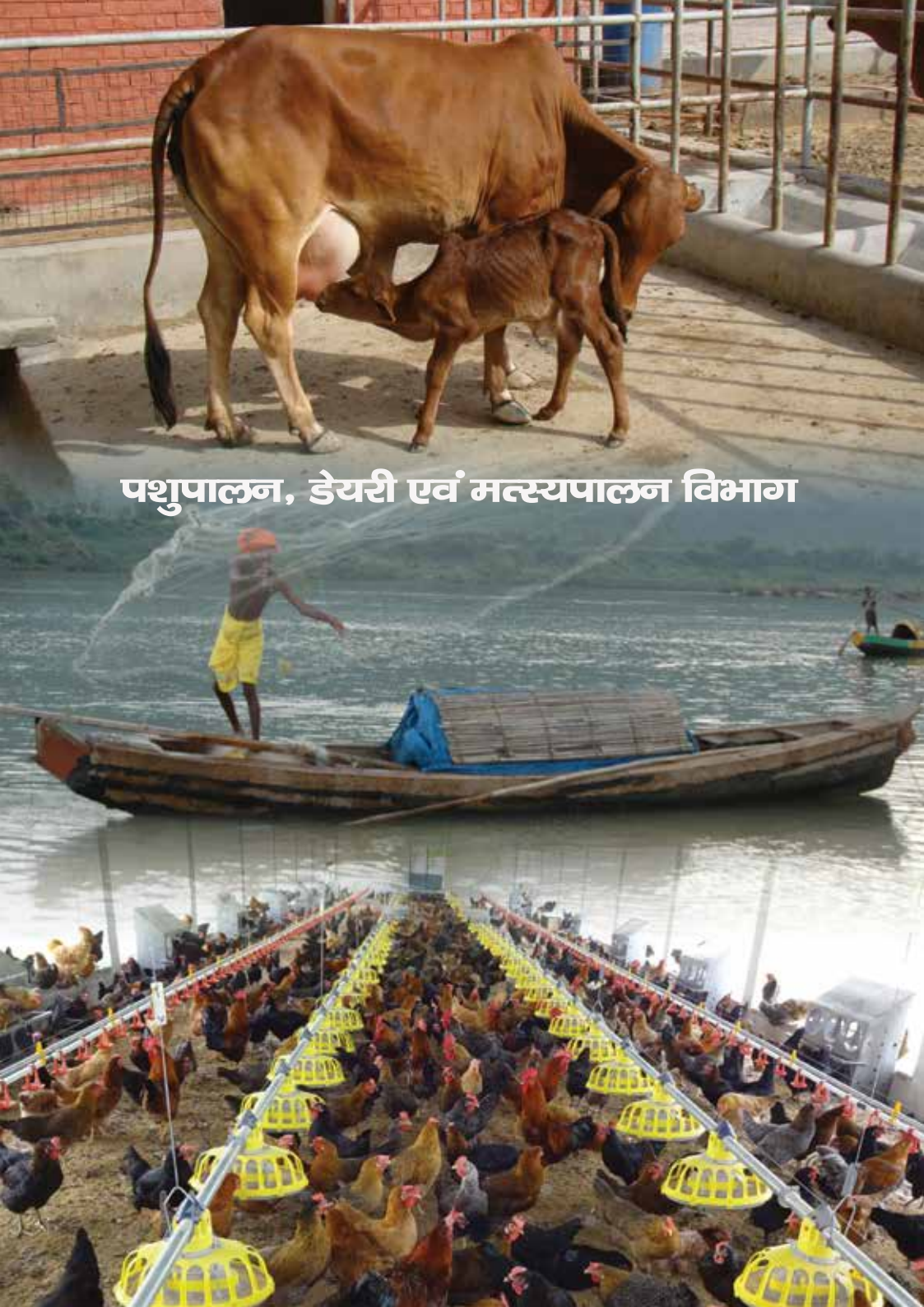

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग

डेयरी विकास : राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- बजट आवंटन में कई गुना वृद्धि के साथ वैज्ञानिक और समेकित रूप से देशी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ की गई है। 2011–14 के मुकाबले पिछले तीन वर्षों के दौरान 13 गुना अधिक बजट आवंटन।
- दो नए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केन्द्र (उत्तर भारत– मध्य प्रदेश में एक तथा दक्षिण भारत– आंध्र प्रदेश में एक) स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
- देश में पहली बार देशी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण के लिए 14 गोकुल ग्राम को मंजूरी दी गई।
- भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और विश्व के कुल दूध उत्पादन में 19 प्रतिशत योगदान करता है।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान डेयरी किसानों की आय में 13.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दुग्ध उत्पादन

2011–14 के मुकाबले 2014–17 में दुग्ध उत्पादन वृद्धि 16.9 प्रतिशत है।

किसानों को अदा की जाने वाली औसत कीमत में वृद्धि

2011–14 के मुकाबले 2014–17 के दौरान डेयरी किसानों की आय में 13.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि

- 2017–18 के लिए 2000 करोड़ रुपए की 'डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)'' नामक कायिक निधि से डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि स्थापित की जाएगी जिसे अगले 3 वर्षों के दौरान 8000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। इस विभाग ने वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन

- दूध उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा डेयरी व्यवसाय को किसानों के लिए और लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने तीन वर्षों की अवधि के लिए 825 करोड़ रुपए के आवंटन से 2015–16 में राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मिशन नामक एक नई योजना प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य पशुपालक के द्वार पर गाय और भैंसों के आनुवांशिक उन्नयन हेतु प्रजनन संसाधनों की उपलब्धता तथा ग्रामीण भारत में बहुद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन की स्वावलंबी व्यवस्था और द्रव नाइट्रोजन की परिवहन और वितरण प्रणाली की सुव्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं :

1. पशुधन संजीवनीः यह एक पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके भाग हैः 1) पशु स्वास्थ्य कार्ड (नकुल स्वास्थ्य पत्र), 2) यूनिक पहचान संख्या और 3) राष्ट्रीय डाटाबेस।
2. उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी असिसटेड प्रजनन तकनीक सहित– इस योजना का उद्देश्य रोगमुक्त मादा बोवाईनों की उपलब्धता को बढ़ाना एवं उन्नत बनाना है।
3. ई–पशुधन हाट का निर्माण– देशी बोवाईन नस्लों के प्रजनकों और किसानों को जोड़ने एवं बोवाईन जर्मप्लाजम के लिए ई–मार्केट की स्थापना।
4. राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्रः तीव्र आनुवांशिक उन्नयन के जरिए देशी नस्लों के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र की स्थापना।

ई–पशुधन हाट के लाभ

- इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को देशी नस्लों संबंधी नस्ल वार सूचना मिल सकेगी। किसान/प्रजनक इस पोर्टल के माध्यम से देशी नस्ल के पशुओं की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। जर्मप्लाज्म के सभी रूपों की सूचना पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। किसान तत्काल इस पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं।
- इस पोर्टल के माध्यम से पशुओं की खरीद और बिक्री में बिचौलियों की भागीदारी समाप्त हो जाएगी। सभी रूपों में जर्मप्लाज्म की खरीद तथा बिक्री संबंधी पोर्टल विकसित डेयरी देशों में भी उपलब्ध नहीं है।

ई–पशुधन हाट वेब पोर्टल

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

- पशुधन बीमा का क्षेत्र और कवरेज बढ़कर 300 जिलों से सभी 716 जिलों में कर दिया गया है। साथ ही, पशुधन बीमा कवरेज का विस्तार करते हुए 2 दुधारू पशुओं से 5 दुधारू पशु/अन्य पशु अथवा 50 छोटे पशु किया गया है।

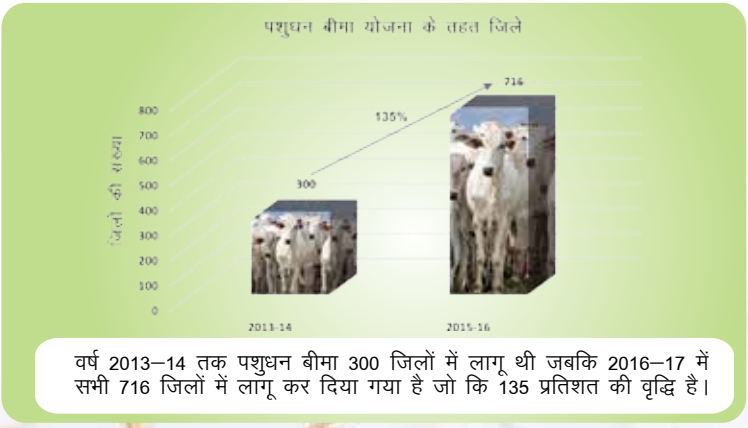

वर्ष 2013–14 तक पशुधन बीमा 300 जिलों में लागू थी जबकि 2016–17 में सभी 716 जिलों में लागू कर दिया गया है जो कि 135 प्रतिशत की वृद्धि है।

- अंडा उत्पादन की वार्षिक विकास दर 5 प्रतिशत है।
- प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 66 अंडे प्रति वर्ष हो गई है।

अंडा उत्पादन

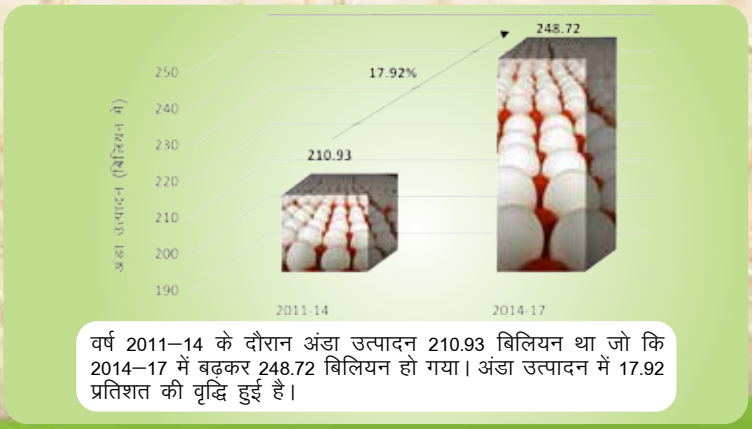

वर्ष 2011–14 के दौरान अंडा उत्पादन 210.93 बिलियन था जो कि 2014–17 में बढ़कर 248.72 बिलियन हो गया। अंडा उत्पादन में 17.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पशुधन स्वास्थ्य

- खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर तीन क्षेत्रों को एफएमडी मुक्त क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है।

खुरपका और मुंहपका रोग के प्रकोप में कमी

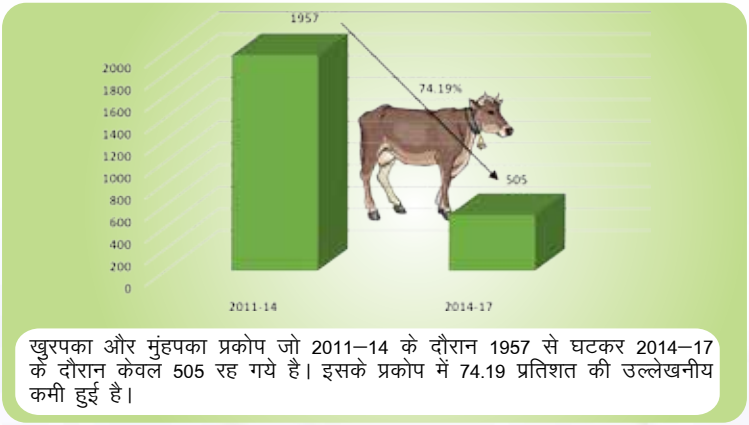

खुरपका और मुंहपका प्रकोप जो 2011–14 के दौरान 1957 से घटकर 2014–17 के दौरान केवल 505 रह गये है। इसके प्रकोप में 74.19 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई है।

- गलघोटू रोग प्रकोप जो 2011–14 के दौरान 698 थे, 2014–17 के दौरान घटकर 300 रह गये हैं।

पशुचिकित्सा शिक्षा

पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि

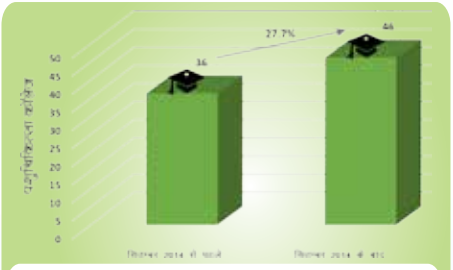

2011–14 की अवधि के दौरान पहली अनुसूची में कॉलेजों की संख्या 36 थी। 2014 से 2017 के दौरान पशुचिकित्सा कॉलेजों की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई है जो कि 27.7 प्रतिशत की वृद्धि है।

पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि

प्रशिक्षित पशुचिकित्सा श्रमशक्ति को पूरा करने के संबंध में, विभिन्न पशुचिकित्सा कॉलेजों में विद्यार्थियों की सीटें 60 से बढ़कर 100 हो गई थी। 17 पशुचिकित्सा कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या 914 से बढ़कर 1334 हो गई है जो कि 45.95 प्रतिशत की वृद्धि है।

- प्रथम अनुसूची में कॉलेजों की संख्या में बढोत्तरी के कारण उत्तीर्ण होने वाले पशुचिकित्सा स्नातकों की कुल संख्या 2011–14 की अवधि के दौरान 2160 थी जो कि वर्ष 2014–17 में बढ़कर 3398 हो गयी है।
- वीसीआई ने मौजूदा पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम, 2008 में संशोधन किया है और अब पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम, 2016 को 8.07.2016 को अधिसूचित किया गया है। संशोधित एमएसवीई में प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क) **वर्तमान पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम में बी.वी.एस.सी और एएच पाठयक्रम में वार्षिक प्रवेश 60 से बढ़ाकर 80 कर दी गई है।**

ख) बी.वी.एस.सी. पाठ्यक्रमों के समय को 5 से बढ़ाकर 5½ वर्ष करने के साथ इंटर्नशिप कार्यक्रम को 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष और पाठ्य कार्य को 4½ वर्ष किया गया।

ग) एससी और एसटी/ओबीसी तथा शारीरिक रूप से विकलांग के लिए आरक्षण नीति को प्रारंभ किया गया है जोकि पूर्व एमएसवीई में नहीं थी।

घ) बी.वी.एससी और एएच पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट घंटों को 179 घंटे से घटाकर 81 घंटे किया गया और पाठ्यक्रम सेमेस्टर के बजाय वार्षिक आधार पर होगा।

ङ) अतिरिक्त पाठ्यक्रम/सिलेबस जैसे खतरा मूल्यांकन, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिन्दु, जोखिम मूल्यांकन, पशु जनित खाद्य के संबंध में स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय आदि को प्रारंभ किया गया है।

मात्स्यिकी–नीली क्रांति

मछली उत्पादन

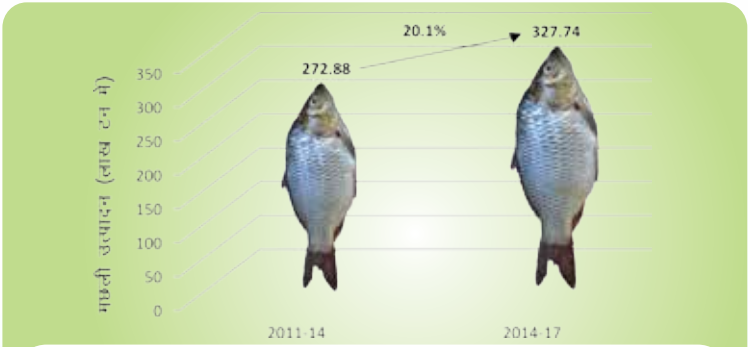

2011–14 के दौरान मछली उत्पादन 272.88 लाख टन था जो कि 2014–17 में बढ़कर 327.74 लाख टन हो गया है। इसमें 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गहन समुद्री मत्स्यन

- विभाग ने 9 मार्च 2017 को नीली क्रांति योजना के मौजूदा घटक समुद्री मात्स्यिकी, अवसरंचना और पोस्ट हार्वेस्ट परिचालन का विकास के तहत ''गहन समुद्री मत्स्यन हेतु सहायता'' नामक उप–घटक को प्रारंभ किया है। यह परम्परागत मछुआरों द्वारा गहन समुद्री मत्स्यन में उद्यम हेतु क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेगा और तुलनात्मक रूप से उच्च आय सृजन के साथ उनकी आजीविका में सहयोग करेगा। उप–घटक का उद्देश्य परम्परागत मछुआरों हेतु भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्षेत्रीय जल के पार हमारे मछुआरों को गहन समुद्र में मत्स्य संसाधनों के दोहन, परिचालन के लिए मध्यम आकार के आधुनिक गहन समुद्री मत्स्यन यानों (डीसमएफबी) को प्रारंभ करना है।

मछुआरा कल्याण

मछुआरों के हितों के मद्देनजर बचत–सह–राहत राशि में वृद्धि

नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन के तहत 3 माह की मत्स्यन निषेध अवधि के दौरान बचत–सह–राहत की राशि में 150 प्रतिशत की वृद्धि करके मछुआरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

- मछुआरा समुदाय हेतु वार्षिक बीमा प्रीमियम को रु. 29.00 से कम करके रु. 20.34 किया गया है।
- आकस्मिक मृत्यु और स्थाई अपंगता हेतु बीमा कवर 1.00 लाख रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. कर दिया गया है।

मात्स्यिकी अवसंरचना विकास

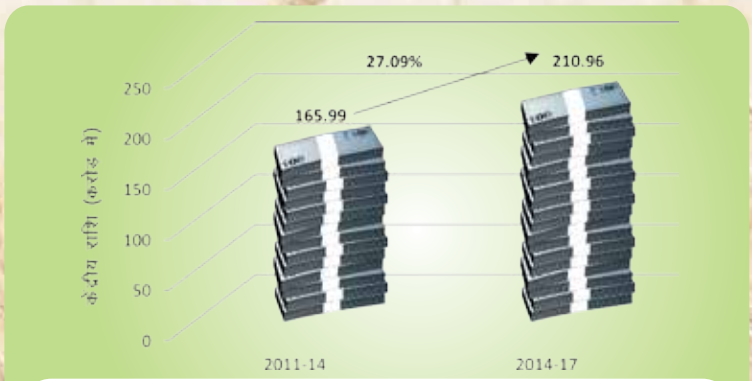

मात्स्यिकी अवसंरचना विकास हेतु जारी किए गए केन्द्रीय राशि में 27.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

व्यापार – हमारी प्राथमिकता

- सभी 6 पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्रों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, और बंगलुरू द्वारा पशुधन और पशुधन उत्पादों के ऑन–लाईन निकासी हेतु एकल खिड़की प्रणाली का कार्यान्वयन।
- पशुधन उत्पादों के आयात हेतु ऑन–लाईन प्राप्ति और एसआईपी आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) वेबसाईट 01.10.2016 से पूर्णतया कार्यान्वित।
- 10 नये अतिरिक्त प्रवेश बिन्दुओं को पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात/निर्यात हेतु का.आ. 948(ई) 22 मार्च, 2017 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- बांग्लादेश से पशुधन और पशुधन उत्पादों के निर्यात/आयात को सुगम बनाने के लिए एक्यूसीएस कार्यालय, पेट्रापोल आईसीपी, पश्चिम बंगाल का उद्घाटन किया जा चुका है।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

कृषि शिक्षा

कृषि शिक्षा का बढ़ता हुआ बजट

पांचवीं संकाय अध्यक्ष समिति द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम

प्रारंभ किए गए नए कार्यक्रम

- बी. टैक (जैव प्रौद्योगिकी)
- बी.एससी. समुदाय विज्ञान
- बी.एससी.खाद्य पोषण तथा डाइटिटिक्स
- बी.एससी. रेशम पालन

कृषि विज्ञान में डिग्री को प्रोफेशनल घोषित किया गया

स्नातक स्तर में पाठ्यक्रमों का व्यापक वितरण

- I वर्ष में पारंपरिक पाठ्यक्रम
- II वर्ष में प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम
- III वर्ष में प्रतिभा आधारित पाठ्यक्रम
- IV वर्ष में ट्रेड आधारित पाठ्यक्रम

अनिवार्य सामान्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए

पांचवी संकाय अध्यक्ष समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन 29 जून, 2016

कृषि विश्वविद्यालयों में खोली गई नई अनुभवजन्य शिक्षण यूनिटें

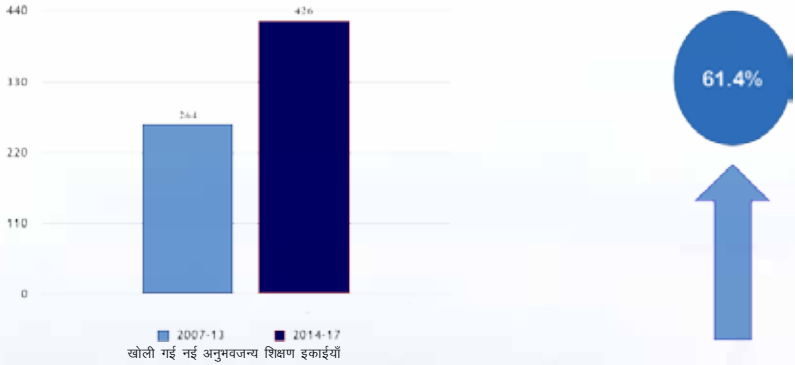

खोली गई नई अनुभवजन्य शिक्षण इकाईयाँ

ये इकाईयां किसानों को प्रशिक्षण के साथ–साथ लाभ कमाने का वास्तविक अनुभव प्रदान कराती हैं।

स्नातक स्तर के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति में दो गुना वृद्धि

- **राशि को रू. 1000/ प्रतिमाह से बढ़ाकर रू. 2000 प्रतिमाह किया गया**
- **लाभार्थियों की संख्या :1351**

नए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

एएनजीआरएयू, आंध्रप्रदेश एवं एसकेएलटीएसएचयू, तेलंगाना प्रत्येक को रु. 122.5 करोड़ जारी किए गए।

पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से किये गये प्रयास

- राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय का उन्नयन कर डॉ0 राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया।
- देश के अग्रणी कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, पूसा की तर्ज पर दो नए संस्थान IARI, झारखंड एवं IARI, असम बनाए जाने हैं, जिसमें IARI झारखंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। IARI, असम का कैबिनेट की मंजूरी के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 26 मई 2017 को शिलान्यास किया जाएगा।

स्टूडेंट रेडी

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 जुलाई, 2015 को आरंभ की गई स्टूडेंट रेडी के दौरान 6 मास की अवधि हेतु सभी विद्यार्थियों के लिए प्रतिमास रु. 3,000 की दर से 2016–17 से अध्येतावृत्ति आरंभ की गई, जो पहले रु. 1000 प्रतिमास थी।

स्टूडेंट रेडी के घटक

1 अनुभवजन्य शिक्षण (ईएल)

2 ग्रामीण कृषिकार्य का अनुभव (आरएडब्ल्यूई)

3 संयन्त्र–सील प्रशिक्षण/औद्योगिक उपकरण/प्रशिक्षुता

4 कौशल विकास प्रशिक्षण

5 विद्यार्थी परियोजना

नेताजी सुभाष–आईसीएआर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

- विश्व के चयनित सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित सक्षम मानव संसाधन का विकास करना। – 79 छात्र
- आईसीएआर–कृषि विश्वविद्यालय तंत्र में विदेशी अभ्यार्थियों को भारत के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों के सुगम्य बनाना जिससे वर्धित भविष्य सहयोग हेतु वैज्ञानिक–दूत का एक पूल तैयार हो। –23 छात्र

वार्षिक 30 अध्येतावृत्ति

- यूएस डॉलर 2000 प्रतिमाह (भारतीय अभ्यर्थियों के लिए) और
- रु. 40000/– प्रतिमाह (विदेशी अभ्यर्थियों के लिए
- नए (फ्रेश) और सेवारत (आईसीएआर–राज्य कृषि विश्वविद्यालय)

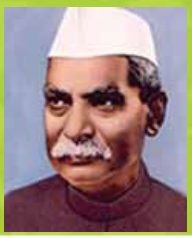

पं. दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना

- 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जैविक कृषि/प्राकृतिक कृषि और गाय आधारित अर्थ–व्यवस्था पर 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम
- रु. 5.35 करोड़ के बजट के साथ 100 केन्द्रों का निर्धारण
- 5 क्षेत्रीय कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन (लखनऊ, कोलापुर, अविकानगर, अमृतसर और झांसी)

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस

देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस घोषित किया गया।

राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना

- यूएस डॉलर 165.0 मिलियन (रू. 1000 करोड़) के व्यय के साथ प्रस्तावित
- विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 लागत हिस्सेदारी–आधार पर पोषित
- योजना की अवधिः छः वर्ष (2016–17 से 2021–22 तक)
- संबंधित विभागों में ईएफसी परिचालित किया गया

चार नए आईसीएआर पुरस्कार

पुरस्कार का नाम (संख्या)	शुरूआत का वर्ष	पुरस्कार का मूल्य
1) आईसीएआर प्रशासनिक पुरस्कार (तकनीकी, प्रशासनिक एवं सहायक श्रेणियों में प्रत्येक के लिए 3 पुरस्कार)	2014	प्रत्येक को रु. 51000/–
2) हलधर जैविक किसान पुरस्कार (1)	2015	रु. 1,00,000/–
3) पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार (1 राष्ट्रीय एवं 11 क्षेत्रीय पुरस्कार)	2016	राष्ट्रीय : रु. 1,00,000/– क्षेत्रीय रु. 51000/– प्रत्येक
4) पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार (1 राष्ट्रीय तथा 11 क्षेत्रीय पुरस्कार)	2016	राष्ट्रीय : रु. 25,00,000/– क्षेत्रीय रु. 2,25,000/– प्रत्येक

कृषि विस्तार

कृषि विज्ञान केन्द्रों में वृद्धि

वर्ष – नये केवीके स्थापित

2014-17 - 32
2012-14 - 07

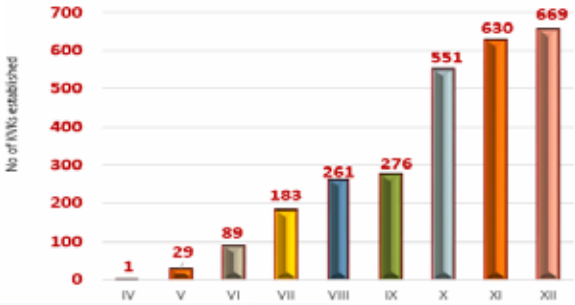

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा दलहन का प्रदर्शन

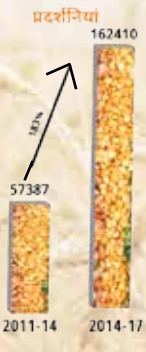

कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा तिलहन का प्रदर्शन

फार्मर फर्स्ट– ज्ञान में वृद्धि करना : प्रौद्योगिकी का एकीकरण

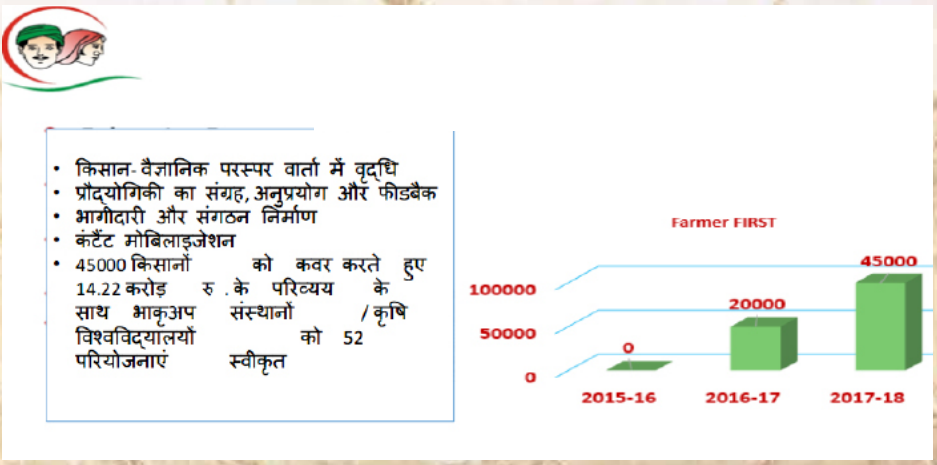

मेरा गाँव मेरा गौरव

- पहचान किए गए 5 गांवों के साथ कार्य कर रहा 4 कृषि वैज्ञानिकों (बहु–विधा) का दल
- किसानों को ज्ञान, कौशल और सूचना में सहायता
- चेतावनियां और परामर्श समय पर जारी करना
- आदानों, सेवा प्रदाताओं आदि के संबंध में सूचना प्रदान करना
- गांवों का विकास करने के लिए विभिन्न विभागों और संगठनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना
- 25000 गांव कवर किए जाएंगे

युवाओं को कृषि की तरफ आकर्षित कर उनकी अभिरुचि बनाए रखना (आर्या)

- ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न कृषि और सम्बद्ध और सेवा क्षेत्रों के उद्यमों की ओर आकर्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना
- प्रसंस्करण मूल्यसंवर्धन, मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर बल
- उद्यमिता विकास और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन
- 25 राज्यों में 25 कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रति जिला 200–300 युवा शामिल हैं

कृषि उन्नति मेला–2016 एवं कृषि उन्नति मेला–2017

कृषि उन्नति मेला का आयोजन वर्ष 2016 एवं 2017 में दो बार किया गया। इन मेलों में भारत की सभी कृषि औद्योगिक कंपनियों ने अपनी सहभागिता दिखाई तथा लगभग 5 लाख किसानों ने मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

उद्देश्य

किसानों को नई किस्मों और नई तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान करना

प्रमुख आयोजन

- फसलों की उत्पादन प्रौद्योगिकियों का सीधा प्रदर्शन
- भा.कृ.अनु.सं. के प्रायोगिक खेतों का किसानों का दौरा
- सब्जियों एवं फूलों की संरक्षित खेती के लिए प्रौद्योगिकियां
- भा.कृ.अनु.सं. एवं निजी कम्पनियों द्वारा कृषि उपकरण एवं मशीनरी का प्रदर्शन एवं बिक्री
- उन्नत पशुओं एवं पशुपालन का सीधा प्रदर्शन
- भा.कृ.अनु.सं. एवं अन्य सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा फसलों के अधिक उपज देने वाले बीजों, सैप्लिंग्स और सिडलिंग्स की बिक्री
- मृदा एवं जल का निःशुल्क परीक्षण
- जैव उर्वरकों और कृषि–रसायनों की बिक्री और प्रदर्शन
- जल बचत के लिए सिंचाई प्रौद्योगिकी
- नवोन्मेषी किसान उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन
- किसान गोष्ठी
- कृषि महिला सशक्तिकरण कार्यशाला

कृषि अनुसंधान

पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई फसल किस्में

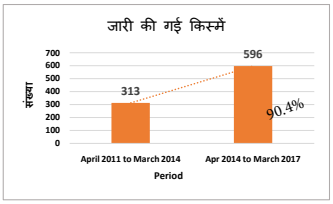

फसल समूह	अप्रैल 2011 से मार्च 2014	अप्रैल 2014 से मार्च 2017
अनाज	184	329
दलहन	43	84
तिलहन	47	92
अन्य	39	91
कुल	313	596

अजैव दबावों के प्रति सहिष्णु/ प्रतिरोधक जारी की गई जलवायु - अनुकूल किस्मों की संख्या

फसल	जनवरी 2012 से मई 2014	जून 2014 से दिसम्बर 2016
अनाज	69	144
तिलहन	38	83
दलहन	33	80
अन्य	21	42
कुल	161	349

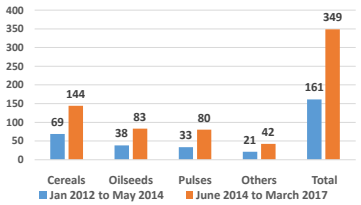

प्रजनक बीज उत्पादन

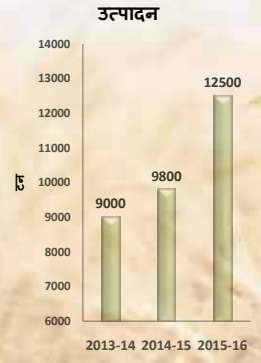

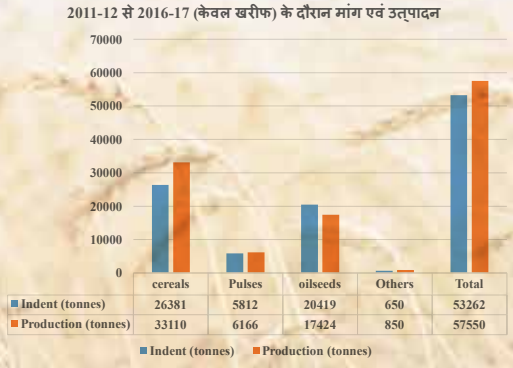

राज्यों के लिए प्रजनक बीजों के उत्पादन में वृद्धि

कृषि आय को दुगुना करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल

घरेलू आकार: 1.20 है. 7 परिवार सदस्य

कृषि फसलें	0.84 ha
बागवानी फसलें	0.22 ha
डेयरी	2 Buffalo + 1 Cow
मात्स्यिकी	0.10 ha
वर्मी- कम्पोस्ट खम्ब	0.01 ha
चार दीवारी - रोपण	12 nos. 4 tier racks
	(200m running length)

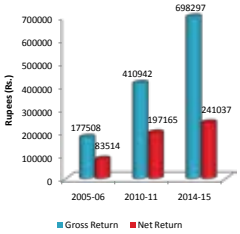

- देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के लिए 45 आईएएफ मॉडल विकसित किए गए
- लाभप्रदता, जीविका सृजन और जोखिम न्यूनीकरण से संबद्ध आईएफएस
- प्रतिकूल मौसम घटना वर्षों के दौरान भी आईएफएस ने अधिक स्थायी आय उपलब्ध कराई
- बहु उद्यम आईएफएस के संवर्धन हेतु एकीकृत योजनाओं की आवश्यकता है
- शुद्ध लाभ (3 वर्षों की आय)रू 2014–15 के दौरान रू. 2.5 लाख
- पुनर्उपयोग: श्रम को छोड़ कर कुल निविष्टियों का 34%
- अतिरिक्त रोजगार का मूल्य: रू. 88,000

जिला आकस्मिक योजना

623 जिला आकस्मिक योजनाएं विकसित की गईं: बागवानी, पशु–धन, कुक्कुट–पालन, मात्स्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मौसम विपदा हेतु प्रौद्योगिकी उपाय

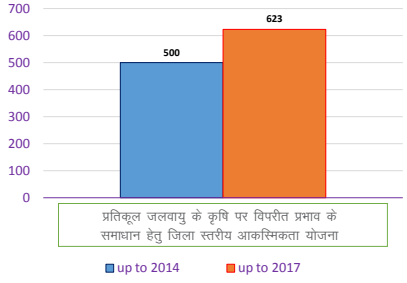

विकसित कृषि मशीनरी के नए प्रोटोटाइप, कृषि प्रसंस्करण केन्द्र एवं आहार परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित

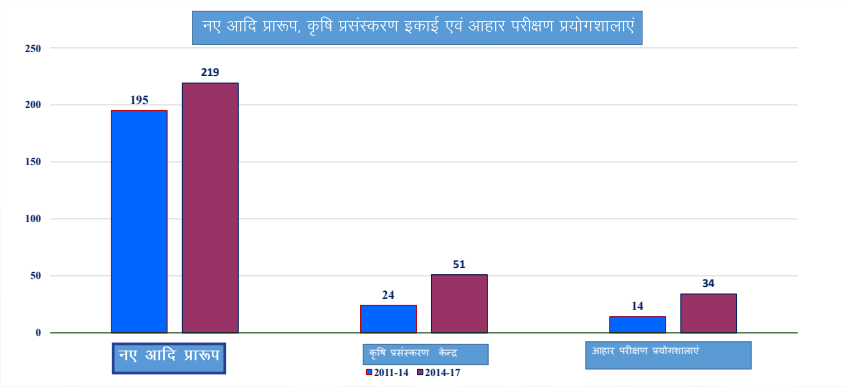

विकसित टीके

- **जोहनेज रोग**
- **पेस्टे देस पेटिटस रोमंथियां (पीपीआर)**
- **गोट पोक्स**
- **इक्विहरपाबोर्ट**
- **क्लासीकल स्वाइन फीवर**

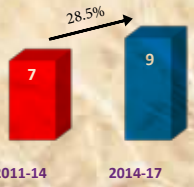

विकसित निदान किटें

वर्ष 2011–14 में 29 निदान किटें विकसित की गई थी जो वर्ष 2014–17 के दौरान 10.3% बढ़कर 32 हो गई हैं।

इलिसा किट – थेलेरिया इक्वि

इलिसा किट – जापानी एनसेफालिटीज

लेटरल फ्लो एस्से – ब्रूसेलिओसिस

लेटरल फ्लो एस्से – ट्राईपानोसोमइवन्सी

पेपर स्ट्रिप एस्से – दूध में नाशीजीवनाशी अवशेष

डीबीटी– ब्रूसेलिओसिस के निदान हेतु इलिसा किटों के विकास हेतु निवेदी को बायोटेक उत्पादन अवार्ड

खुले–समुद्र में पिंजरा जलजीव पालन

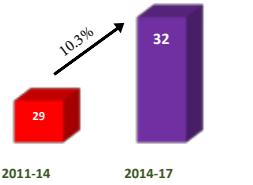

- कोबिया (*रैकीसेन्ट्रोन कनाडम*) एवं सिल्वर पोम्पानो (*ट्रैकीनोटस ब्लोशी*) का समुद्री पिंजरा संवर्धन – प्रौद्योगिकी प्रदर्शन
- छह महीने में 3.0 टन के औसत उत्पादन स्तरों का प्रदर्शन किया गया (6 मी व्यास x 6 मी गहराई) : 25–30 कि ग्रा / मी^{3}
- कोबिया और पोम्पानों के लिए उत्पादन लागत 180 रू0/कि.ग्रा. है। फार्म गेट मूल्य – 350 रू0/कि.ग्रा. (कोबिया) और 300 रू0/कि.ग्रा. (सिल्वर पोम्पनो)
- भा.कृ.अ.प.-सीएमएफआरआई की तकनीकी सहायता से भारत के पूरे तट के साथ 1058 केज स्थापित किए गए

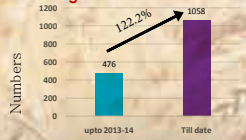

कृषि प्रौद्योगिकी विकास

विगत 3 वर्षों के दौरान भाकृअप द्वारा विकसित उल्लेखनीय नवीन फसल किस्में एवं प्रौद्योगिकियां

चिह्नकों की सहायता से चयन का उपयोग कर धान की अधिक उपज देने वाली तथा सूखा (1), ब्लास्ट रोग (3) एवं जीवाणु पर्ण झुलसा रोग (5) के लिए प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई

उच्च प्रोटीन अंश (10.3%) युक्त धान की किस्म (सीआर धान 310) विकसित की गई

उच्च जिंक अंश (22पीपीएम) युक्त धान की किस्म (डीआरआर धान 45) विकसित की गई

दोहरे उपयोग वाले गेहूं (दाना एवं चारा) की किस्म (वीएल गेहूं 829) विकसित की गई

न्यून इरूसिक अम्ल (<2%) युक्त सरसों की किस्म पूसा सरसों 30 विकसित की गई

भाकृअप द्वारा तीन बीटी कपास कृषिजोपजातियों; पएयू–1, आरएस–2013 एवं एफ–1861 की पहचान कर उन्हें वाणिज्यिक रूप से जारी करने का अनुमोदन किया गया है।

केन्द्रीय कपास अनुसन्धान संस्थान नागपुर ने बीटी–6 कपास की एक प्रजाति सीआईसीआर–आरएस 2013 बीटी सेल विकसित की है जिससे 3046 किलो प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त हुई है जो सर्वाधिक है।

एग्रो–वोल्टैक सिस्टम/सौर कृषि (सोलर फार्मिंग)

एग्री-वोल्टैक सिस्टम

जमीन के एक टुकडे से एक ही साथ पीवी मॉड्युल के जरिये फसल उगाना तथा बिजली पैदा करना

मॉडल क्षेत्र: 1 हेक्टेयर

- सौर पीवी सृजन क्षमता: 0.5 मेगावाट
- प्रति दिन बिजली सृजन: 2500 किलोवाट प्रति घंटे
- निवेश:2.5 करोड़ रूपये
- बिजली से आय सृजन: लगभग 45 लाख रूपये वार्षिक
- प्रणाली की आयु: 25 वर्ष
- 7 वर्षों में कुल लागत रिकवरी
- मूंग उपज:4 क्वि./हेक्टेयर

सौर कृषि प्रणाली में स्व-स्थाने मृदा आर्द्रता संरक्षण के लिए रिज फरो बीज ड्रिल

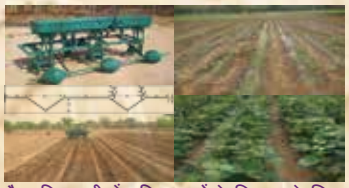

सौर कृषि प्रणाली में कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए सोलर पीवी स्प्रेयर का विकास

शूकर एवं कुक्कुट की विकसित की गई नई उन्नत नस्लें

- रानी, आशा, एचडी-के 75 एवं जारसुक नामक शूकर की नई संकर नस्लें विकसित की गईं

- कुक्कुट पक्षियों की तीन नई नस्लों (कामरूप, नर्मदानिधि एवं झारसिम) का विकास किया गया

नई पीढ़ी के मत्स्य जलयानों (फिशिंग वैसल) का विकास

ट्रावलिंग, गिलनेटिंग एवं लांगलाइनिंग के लिए बहु-उद्देशीय मत्स्य जलयान

- नई पीढ़ी के ईंधन-किफायती एवं बहु-उद्देशीय मत्स्य जलयान का विकास किया गया और इसे चालू किया गया

नवीन आईसीटी (सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी) ऐप्स एवं पोर्टल

वेब पोर्टल–कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान नेटवर्क
पूसा कृषि– प्रौद्योगिकी मोबाइल ऐप
मोबाइल ऐप ''राइसएक्सपर्ट''
ई– कपास नेटवर्क और प्रौद्योगिकी दस्तावेजीकरण
नाशीजीव और रोगों के लिए दलहन विशेषज्ञ
ई–नशीजीव निगरानी और बागवानी फसलों के लिए परामर्शदाता व्यवस्था
ऑनलाइन नाशीजीव मॉनीटरिंग और सलाहकारी सेवा
नाशीजीव पूर्व चेतावनी ऐप्लिकेशन
कृषि– डिजिटल डाटा पोर्टल

जय किसान
जय विज्ञान

तीन वर्ष का रोडमैप (2017–2019)

सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। इस कार्य के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 2017–18 से 2019–20 की अगली तीन वर्ष की अवधि में निम्नलिखित की शुरूआत करेगा तथा उसे कार्यान्वित करेगाः

1. कृषि आदानः

- 1.1 बीजः बीजग्राम कार्यक्रम का विस्तार 30,000 गांव से 60,000 गांव तक तक किया जाएगा तथा 500 बीज उत्पादन और प्रसंस्करण यूनिट पंचायत स्तर पर स्थापित की जाएंगी।
- दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 150 बीज हब के जरिए 1.5 लाख क्विंटल संकर बीज का उत्पादन किया जाएगा।
- बीजों के प्रभावी विनियमन और अनिवार्य पंजीकरण हेतु बीज विधेयक पारित किया जाएगा।
- 1.2 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधनः मृदा स्वास्थ्य कार्डों के वितरण का वर्तमान चक्र पूरा किया जाएगा तथा अगला चक्र मई, 2017 से शुरू किया जाएगा तथा मई, 2019 में पूरा किया जाएगा। तीसरा चक्र उसके बाद शुरु होगा।
- स्थानीय उद्यमियों द्वारा 1000 मिनी प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्ट–अप के जरिए शीघ्र मृदा परीक्षण वाले साधनों का विकास किया जाएगा।
- किसी भी समय/किसी भी स्थल/किसी भी फसल की उर्वरक सिफारिशों को सृजित करने के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया जाएगा।
- 70 अतिरिक्त जिलों में कस्टमाइज/सूक्ष्म पोषक तत्वों से लेपित उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- समस्याग्रस्त मृदाओं के लिए (क्षारीय, लवणीय और अम्लीय) के लिए 80,000 हैक्टेयर भूमि का सुधार किया जाएगा।

1–3 जलः नाबार्ड में 5000 करोड़ की समर्पित निधि का कार्यान्वयन किया जाएगा तथा सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 4.8 मिलियन क्षेत्र कवर किया जाएगा।

2 उत्पादकता सुधार और विविधीकरणः

- फसलः वर्ष 2020 तक 3 मिलियन हैक्टेयर

- क्षेत्र कवर करने के लिए दलहन और तिलहन हेतु चावल की परती क्षेत्रों के उपयोग के जरिए प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में फसल गहनता को बढ़ाया जाएगा।
- बार–बार सूखा पड़ने वाले जिलों (100 संख्या) में एनआईसीआरए के अपस्केलिंग द्वारा जलवायु सह–फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा में खेती के क्षेत्र को 3 लाख है. से 3.75 लाख है. करके परती भूमि में ऑयल पॉम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इस कार्यक्रम से कच्चे पाम ऑयल उत्पादन को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख टन किया जाएगा।
- वर्ष 2019–20 तक दलहन उत्पादन को 24 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा।

(ख) बागवानीः वर्ष 2019–20 तक पुष्पा , मसालों और सुगंधित पौधों सहित बागानी अर्थात फलों, सब्जियों, बागानों और अन्य फसलों के तहत 4.5 लाख हैक्ट्येर क्षेत्र लाना तथा 2019–20 तक 1.2 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में अधिक मूल्य वाली फसलों के लिए संरक्षित खेती को बढ़ाना।

- फसल पश्चात् अवसरंचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 लाख मी. टन शीतागार, 1000 पैक हाउस तथा 150 राइपनिंग चैबर्स की स्थापना की जाएगी।
- काजू खेती के तहत वर्तमान क्षेत्र को 10.3 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 11.5 लाख हैक्टेयर किया जाएगा तथा 3 वर्षों की अवधि में इसके उत्पादन को वर्तमान क्षेत्र 6.7 लाख टन से बढ़ाकर 9 लाख टन किया जाएगा।
- नारियल, ऑयलपाम और सुपाड़ी में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में अंतः फसल के रूप में कोको उत्पादन के तहत क्षेत्र को वर्तमान 78,000 हैक्टेयर से बढ़ाकर दो वर्षों में 100,000 हैक्टेयर किया जाएगा।
- दिसंबर, 2018 तक केसर पार्क, राष्ट्रीय केसर मिशन के तहत पूरा किया जाएगा।
- क्रॉस परागित फसलों में परागण सहायता के लिए बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर राज्यों में समेकित मधुमक्खी विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
- दूध सहकारी समितियों के जरिए शहद के संग्रह और विपणन के लिए दिल्ली में शहद का सफल ब्रांड शुरू किया गया है। इस पहल था दो और राज्यों (गुजरात और राजस्थान) में दूध संघों के जरिए एनबीबी द्वारा और आगे विस्तार किया जाएगा।

2.3 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधनः कृषि वानिकी मिशन (हर मेड़ पर पेड़) के तहत 2019–20 तक कृषि वानिकी (हर मेड़ पर पेड़) के तहत 3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लगाया जाएगा।

2.4 वर्षा सिंचित क्षेत्र विकासः अन्य 4 अधिदेशों के अलावा शुष्क भूमि खेती हेतु ज्ञान के भण्डार के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरडीए) का पुनरुद्धार किया जाएगा। अक्तूबर, 2017 तक 15 सर्वाधिक संवेदनशील सूखा संभावित जिलों के लिए कार्य योजनाओं को तैयार किया जाएगा तथा उपर्युक्त कार्यकलाप शुरु किए जाएंगे।

2.4 जैविक कृषिः किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के जरिए 2.5 लाख हैक्टेरयर में जैव कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।

- परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार कलस्टर आकार को 20 हैक्टेयर से बढ़ाकर 1000 हैक्टेवयर किया जाएगा (पूर्वोत्तर राज्यों हेतु मिशन जैव मूल्यू श्रृंखला विकास के तहत 500 हैक्टेयर से 1000 हैक्टेयर) ताकि कुशलतापूर्वक विपणन किया जा सके तथा जैव कृषि की क्षमता का इस्तेवमाल किया जा सके।

3. विपणन, भंडारण एवं अन्य उत्पादन पश्चात् अवसंरचनाः मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू करने के लिए प्रयास।

- अक्तूबर, 2017 तक मॉडल संविधा कृषि अधिनियम, 2017 जारी करना।
- अक्तूबर, 2017 तक 'वेयर हाउस भंडारण और वेयर हाउस रशीद आधारित रेहन ऋणप्रणाली' पर दिशा–निर्देश तैयार करना।
- मार्च, 2018 तक ई–नाम प्लेटफार्म पर 585 कृषि मंडियों को लाना ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा इंटर–मार्केट कारोबार को समेकित करना।
- देश में शुष्क और शीतागार अवसंरचना का मानचित्र तैयार करना तथा गूगल पर उत्पादकों और अन्य साझेदारों को सूचना प्रदान करना।
- ग्रामीण भंडारण योजना के तहत वित्तीय सहायता को मांग आपूर्ति से उत्पन्न जिला भंडारण क्षमता से जोड़ना।
- 4. ऋण और फसल बीमाः
- कृषि ऋणः
  - वर्ष 2018–19 तक अल्पावधिक ऋण के तहत छोटे और सीमांत किसानों के कवरेज को वर्तमान में 43 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक बढ़ाना।
  - देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में

क्रेडिट एब्जोर्पशन पर विशेष ध्यान।

- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण।
  - वर्ष 2019–20 तक देश में सभी 63,000 पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण पूरा करना।
- फसल बीमाः
  - पीएमएफबीवाई और डब्ल्यूबीसीआईस के तहत सकल फसली क्षेत्र (जीसीए) के कवरेज को वर्तमान के 30 प्रतिशत (2016–17) से बढ़ाकर 2017–18 और 2018–19 तक क्रमशः 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत किया जाएगा।

5. पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी

5.1 डेयरीः

- 1.1 लाख गायों के उत्पादन के लिए 50 एम्ब्रयो ट्रांसफर प्रयोगशाला की स्थापना करके स्वदेशी नस्लोंनन डिस्क्रिप्ट गायों को उन्नत बनाना।
- गोकुल मिशन के तहत वर्ष 2019–20 तकृ कृत्रिम निषेचन को तिगुना करके 80प्रतिशत तक कवरेज किया जाएगा। (एआई कवरेज)।
- खुर और मुंहपका रोग (एफएमडी) और ब्रुसेलोसिस हेतु 100 प्रतिशत टीकाकरण, पशु संजीवनी एप्प और हेल्थ कार्ड के जरिए टीका लगे हुए पशुओं की मॉनिटरिंग करना।
- दूध खरीद अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना।
- मार्च, 2018 तक थोक दूध संकलन को 16,000 गांव से बढ़ाकर 50,000 गांव करना।
- डेयरी अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ) के तहत पुरानी (10 से 30 वर्ष) सहकारी डेयरियों को आधुनिक बनाना।
- मार्च, 2019 तक 5 राज्यों को रोग मुक्त घोषित करने के लिए कार्य करना रूस, मध्य पूर्व और एशिया में निर्यात मंडियों का पता लगाना।
- दूध सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों के जरिए प्रतिवर्ष 10,000 हेक्टेयर की दर से चारा विकास को बढ़ावा देना।

5.2 मत्स्यपालन

- 20 राज्यों में 774 हैचरियां स्थापित करके उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ–साथ इनमें प्रतिवर्ष 1140 करोड़ फिंगर लिंगो की शुरूआत करना और 8 राज्यों 100 हैचरियों में ऑर्नामेंटल मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।
- 20,000 केज कल्चर को बढ़ावा देना और इसके साथ–साथ 500 पुनः प्रचालक मत्स्य पालन का भी संवर्धन करना।
- 1600 बाटम ट्रोलरों को हटाकर उनकी

जगह टूना लांग लाईनर को प्रतिस्थापित करना एवं गहरे समुद्र में मत्स्य प्रग्रहण को बढ़ावा देना। 2800 समुद्रीय केजों के प्रारंभ और अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप की द्वीप विकास योजना 44 करोड़ रु. के निवेश का कार्य करना।

- तिलेपिया केज कल्चर के द्वारा असम और नागालैंड में तिलेपियधान मत्स्य फार्मिंग को बढ़ावा देना केरल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में धान के खेत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना।

5.3 छोटे पशु (बकरी, भेड़, सूअर और कुक्कुट)

- राष्ट्रीय पशुपालन मिशन (एनएलएम) के तहत 2,50,000 भेड़ों और 5 लाख बकरियों का उन्नयन करके 2 लाख किसानों के लाभान्वित करना।
- राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की तर्ज पर राष्ट्रीय पशु पालन अभिकरण (एनएलडीए) स्थापित करना।
- राष्ट्रीय पशुपालन मिशन के तहत 18,000 बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों को ब्रॉयलरों/लेयर फार्मों में बदलना।

6.0 कृषि विस्तार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:

- मोबाइल और वेब आधारित सेवाओं के जरिए मानव शक्तिड आधारित विस्तार सेवा के अभिन्न रूप में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ–साथ उसके समुचित उपयोग को संवर्धित करना।
- किसानों तक सहज पहुंच प्रदान करने के प्रयोजनार्थ किसान काल सेंटरों की सेवाओं को विस्तारित करना (2018–19)।
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (एटीएमए) सहित विभिन्न विस्तार सेवाओं में कंपनियों द्वारा निवेश करने संबंधी मार्ग को प्रशस्त् करने के बारे में प्रावधान करना ताकि ये कंपनियां आयकर अधिनियम (2018–19) की धारा 35 सीसीसी के तहत कर का लाभ प्राप्त कर सकें।
- कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित लाभ प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कृषि अनुप्रयोग कार्यक्रम को व्यापक मंच के रूप में शुरू करना।
- फसल कटाई प्रयोगों की प्रभावकारिता, गति और दक्षता में सुधार लाने के लिए अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के साथ–साथ दिशा–निर्देशों में निर्धारित समय–सीमा के अनुसार किसानों द्वारा किए गए दावों का समय पर निपटान करना। इस कार्य को 2017–18 तक निष्पादित किया जाना है।

अन्य कार्य निष्पादन

– बहुराज्य समितियों को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए बहुराज्य ऋण सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में आवश्यक संशोधन करना।

– 2017–18 तक 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ केंद्रीय क्षेत्रीय सहकारी पंजीयक के स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना करना। इससे प्रशासन कार्य में सुधार आने के साथ–साथ पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण कार्य भी प्रभावी रूप से निपोदित होगा।

7.0 कृषि अनुसंधान कार्यः

- आईसीएआर उपज में सुधार लाने तथा फसलों पर पड़ने वाले विभिन्न दबावों में सहिष्णुता संबंधी संतुलन स्थापित करने के लिए जीनोमिक्सजीन एडिटिंग प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान कार्य करेगा।
- पोषाहारीय तत्वों से समृद्ध आहार (प्रोटीन, जिंक, विटामिन–ए) के लिए जैव सशक्तीकरण कार्य पर अनुसंधान कार्य किया जाएगा।
- जैविक खाद के लिए पशु आहार और माइक्रोबियल कंसोर्शिया आधारित परिवर्तन के लिए लीगनोसेलुलोसेस के विघटन कार्य पर ध्यान केंद्रित करके फसल अपशेष वैज्ञानिक प्रबंधन अनुसंधान के जरिए फसल अपशेषों को जलाने संबंधी समस्या का निदान करना।
- लैंगिक वीर्य उत्पादन से संबंधित देशी प्रौद्योगिकी को विकसित किए जाने के साथ–साथ पशुओं के लिए थर्मो सहिष्णु टीकों के विकास पर अनुसंधान कार्य किया जाएगा।
- लंबे रेशे वाली कपास और अधिक उत्पादन देने वाली जूट की किस्में लाई जाएंगी।
- इस विषय पर सुव्यवस्थित अनुसंधान कार्य करने के लिए आईसीएआर की 75 स्कीमों को 35 थीमेटिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएंगा।

8.0 सुशासन कार्य तंत्र

- सुशासन के आधार के रूप में निम्नांकित को अंगीकार करनाः
  – मंत्रालय की सभी स्कीमों के लिए
  – आधार के द्वारा पहचान

    एसईसीसी/ग्राम सभा के माध्यम से पात्रता

    छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान

    एसएचजी, सहकारी समितियों और एफपीओ के माध्यम से एकीकृत कार्य निष्पादन

    आईटी, डीबीटी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से जवाबदेही तथा जीपीएस द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा।

मुख्य दिवस

1.	विश्व वानिकी दिवस	21 मार्च
2.	विश्व पशु चिकित्सा दिवस	अप्रैल माह का अंतिम शनिवार
3.	विश्व दुग्ध दिवस	1 जून
4.	राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस	10 जुलाई
5.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस	16 जुलाई
6.	विश्व शहद दिवस	20 अगस्त
7.	विश्व नारियल दिवस	2 सितम्बर
8.	विश्व अंडा दिवस	अक्टूबर माह का दूसरा शुक्रवार
9.	राष्ट्रीय महिला किसान दिवस	15 अक्टूबर
10.	विश्व खाद्य दिवस	16 अक्टूबर
11.	विश्व मात्स्यिकी दिवस	21 नवम्बर
12.	राष्ट्रीय दुग्ध दिवस	26 नवम्बर
13.	राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस	3 दिसम्बर
14.	विश्व स्वायल दिवस	5 दिसम्बर
15.	जय किसान जय विज्ञान सप्ताह	23–29 दिसम्बर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

वेबसाइट: http://agriculture.gov.in